

बी डी एल सीएसआर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2021-22)



Submitted to



Submitted by



Shameerpet, Hyderabad



Acknowledgement

We are thankful to the executives of Bharat Dynamics Limited for their valuable inputs and coordination in conducting the Impact Assessment Study of 03 CSR projects of Bharat Dynamics Limited for FY 2021-22. On behalf of the IPE CSR Team, we extend our gratefulness to Commode A Madhavarao (Retd.), Chairman and Managing Director, BDL for providing us the opportunity to conduct the study.

A report of this nature requires an active association of professionals from the host organization. We express our heartfelt gratitude to Shri N Satyanarayana, Head-HR/CSR, Shri A. Sathesh Chakravarthi, DGM C-HR (TA&OD), and Smt A Nagalakshmi, DM C-HR (CSR) for providing us with the necessary support in gathering the data and completing the work on time.

Prof. S. Sreenivasa Murthy

Director, Senior Professor and NLCIL Chair Professor on CSR

Dr. J. Kiranmai

Head - Centre for CG and CSR, IPE

कार्यकारी सारांश	4
अध्याय I कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी: एक अवलोकन	9
अध्याय II भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इसकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में	11
अध्याय III अनुसंधान पद्धति और दृष्टिकोण	13
अध्याय IV परियोजनावार विश्लेषण	15
परियोजना 1: विजयनगरम के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम	
परियोजना 2: राजन्ना सिरसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण	
परियोजना 3: नौसेना अस्पताल, दिल्ली में कोविड से संबंधित उपकरणों की खरीद	
परियोजना 4: भानूर गांव में जिला परिषद हाई स्कूल का निर्माण	
परियोजना 5: लखनऊ में कोविड अस्पताल के निर्माण में योगदान (2021-22)	
परियोजना 6: सैन्य अस्पताल, सिकंदराबाद और ईएसआईसी अस्पताल, सनत नगर, हैदराबाद में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का सस्थापन	
परियोजना 7: ईएसआईसी, सनत नगर, हैदराबाद में कोविड पृथक्करण सुविधाओं की स्थापना	

कार्यकारी सारांश

बीडीएल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बीडीएल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च कर रही है। सीएसआर के तहत मुख्य ध्यान क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा और साक्षरता, कौशल विकास और स्वच्छता आदि हैं। बीडीएल ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिलों / अल्पविकसित क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों को शुरू किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर बजट ₹ 1812.61 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

परियोजना-वार प्रभाव नीचे दिया गया है

परियोजना 1: विजयनगरम में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं

विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण और सीखने के माहौल को बढ़ाने के उद्देश्य से, विभिन्न हितधारकों, जिसमें जन प्रतिनिधि, जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल थे, ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर स्मार्ट कक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर धन सुरक्षित किया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बीडीएल ने विजयनगरम जिले में 34 प्राथमिक और 6 ऊपरी प्राथमिक स्कूलों में 40 स्मार्ट कक्षा प्रणालियों की स्थापना के लिए ₹ 100 लाख की सीएसआर वित्तीय सहायता प्रदान की।

परिणाम: बीडीएल ने विजयनगरम जिले के चयनित 40 सरकारी स्कूलों में 40 KYAN स्मार्ट कक्षा प्रणालियों को स्थापित करके परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त किया। इस परियोजना से कुल 2500 प्राथमिक और ऊपरी प्राथमिक स्कूल के छात्रों को लाभ हुआ, जो विविध विषय सामग्री के साथ जुड़े और प्रतिदिन स्मार्ट कक्षा सत्रों में भाग लिया। नतीजतन, स्कूलों ने प्रतिदिन 3-4 स्मार्ट कक्षा सत्र आयोजित किए, जिससे छात्रों को समृद्ध शैक्षिक अनुभव प्रदान हुए और उनकी मूलभूत संख्यात्मक कौशल, पर्यावरण विज्ञान अवधारणाओं की समझ, साथ ही अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में प्रवीणता में वृद्धि हुई।

प्रभाव: इस परियोजना ने विजयनगरम जिले, आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा शिक्षण और सीखने के माहौल को बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा मानकों में सुधार, स्कूल नामांकन में वृद्धि, अनुपस्थिति में कमी और सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि हुई।

परियोजना 2: राजन्ना सिरसिल्ला के सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों का निर्माण

लड़कियों के शौचालय सुविधाओं के महत्व को पहचानते हुए, राजन्ना-सिरसिल्ला जिले में जिला मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल), एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन से सीएसआर धन सहायता सक्रिय रूप से मांगी। उनके प्रयास सफल रहे क्योंकि उन्हें ₹ 200 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग 39 चयनित सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों के निर्माण के लिए किया गया। इन शौचालयों का निर्माण केवल बीडीएल की उदार वित्तीय सहायता के कारण संभव हुआ। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू हुई और 2021-22 तक पूरी हुई।



परिणाम: इस परियोजना का उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया क्योंकि इसने राजन्ना-सिरसिल्ला जिले में स्थित 39 सरकारी स्कूलों में स्कूली बच्चों के लिए विशेष रूप से शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित कीं। नतीजतन, सरकारी स्कूलों में उपलब्ध शौचालय सुविधाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में, कुल 3000 स्कूली बच्चे, लड़के और लड़कियां, प्रतिदिन शौचालय सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

प्रभाव: राजन्ना-सिरसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों के निर्माण ने महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति दरों में सुधार और स्कूल छोड़ने की दरों में कमी शामिल है। यह लाभकारी प्रभाव स्कूली बच्चों के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित अलग शौचालयों की उपलब्धता के कारण है, जो उनके बीच गरिमा और गोपनीयता की भावना को बढ़ावा देता है। परिणामस्वरूप, स्कूली बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना ने युवा छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ाया है।

परियोजना 3: नौसेना अस्पतालों, दिल्ली में कोविड संबंधित उपकरणों की खरीद

बीडीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर के कई भारतीय नौसेना अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन चिकित्सा उपचारों की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करना था। बीडीएल के सीएसआर धन के माध्यम से प्रत्येक नौसेना अस्पताल के लिए अधिग्रहित चिकित्सा उपकरणों का विवरण, जिसकी राशि 300 लाख रुपए थी। भारतीय नौसेना बेनेवोलेंट (परोपकारी/कल्याण) ने विभिन्न चिकित्सा उपकरण खरीदे।

परिणाम: बीडीएल ने इस परियोजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें पांच INHS अस्पतालों, एक INS अस्पताल और एक डाइविंग स्कूल अस्पताल की चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न चिकित्सा उपकरण, डिवाइस और सुविधाएं प्रदान की गईं। परिणामस्वरूप, इस पहल ने कोविड-19 के उपचार प्रोटोकॉल में उल्लेखनीय सुधार किया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके आश्रितों के जीवन को बचाया गया जो संक्रमित थे। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना ने इन अस्पतालों में उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के माध्यम से आउटपैशेंट, इनपैशेंट, आपातकालीन और सर्जिकल उपचारों की क्षमता को बढ़ाया।

प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने भारतीय नौसेना अस्पतालों में उपचार सुविधाओं के विकास को तेज करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। इस परियोजना ने चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये अस्पताल भविष्य में होने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति को संबोधित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों, उन्नत उपकरणों और बेहतर सुविधाओं की बढ़ी हुई उपलब्धता ने आपातकालीन उपचारों के लिए आवश्यक समय में उल्लेखनीय कमी की है। परिणामस्वरूप, उन्नत सुविधाओं ने न केवल अस्पताल सेवाओं की समग्र प्रभावशीलता में सुधार किया है, बल्कि भारतीय सेना और उनके आश्रितों से जुड़े कई लोगों के जीवन की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान की गई प्रगति ने सैन्य ढांचे के भीतर स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए एक नया मानक स्थापित किया है, जो भविष्य की किसी भी स्वास्थ्य संकट के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित करता है।

परियोजना 4: भानुर गांव में जिला परिषद हाई स्कूल का निर्माण

जिला परिषद हाई स्कूल (ZPHS), भानुर, 1989 में एक सह-शिक्षा स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। यह शैक्षणिक संस्थान तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले में स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र, भानुर गांव में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली

को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में, स्कूल में कुल 145 छात्रों का नामांकन है, जिसमें 75 लड़के और 70 लड़कियाँ शामिल हैं। शिक्षण स्टाफ में 9 सदस्य हैं, जबकि 3 गैर-शिक्षण स्टाफ सदस्य हैं। वर्षों से, स्कूल ने उल्लेखनीय शैक्षणिक सफलता हासिल की है। हालांकि, इसे कक्षा अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, बीडीएल ने ₹ 324 लाख की लागत से एक स्कूल भवन का निर्माण किया और आवश्यक सुविधाएं प्रदान कीं। यह परियोजना फरवरी 2020 में शुरू हुई और मार्च 2022 तक पूरी हुई।

परिणाम: इस परियोजना ने कक्षा VI से X तक के 145 छात्रों के लिए सीखने को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाकर अपने उद्देश्य को बड़ी प्रभावशीलता के साथ पूरा किया। स्कूल भवन के निर्माण के बाद, कक्षा निर्देश, पाठ्येतर गतिविधियों, खेल प्रावधानों, दोपहर के भोजन के दौरान छात्र सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच और शौचालय सुविधाओं में सुधार देखा गया। इन प्रावधानों ने शैक्षिक मानकों और छात्र सुविधाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

प्रभाव: बीडीएल द्वारा भानुर में जिला परिषद हाई स्कूल में स्कूल भवन के निर्माण की शुरुआत ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जैसे स्कूल नामांकन में वृद्धि, छात्रों की अनुपस्थिति में कमी और छात्रों के बीच शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि। इसके अतिरिक्त, इस प्रयास ने स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, पौष्टिक मध्याह्न भोजन और खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करके बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके अलावा, भानुर गाँव में निष्पादित इस परियोजना ने न केवल शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन लाए हैं, बल्कि निवासियों के बीच भविष्य के लिए आशा और आशावाद की भावना भी पैदा की है। यह शिक्षा और समुदाय-संचालित पहलों के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उत्थान और सशक्त बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

परियोजना 5: लखनऊ में कोविड अस्पताल में योगदान

2021 में, कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बीच, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक पूर्ण सुसज्जित अस्थायी कोविड केंद्र स्थापित करने के लिए सक्रिय उपाय किए। इस पहल, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी अस्थायी कोविड केयर सेंटर रखा गया, महामारी की दूसरी लहर के गंभीर प्रभाव को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में थी। केंद्र के लिए स्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में आवंटित किया गया था, और निर्माण की समग्र जिम्मेदारी डीआरडीओ ने ली, जिसमें मुख्य निर्माण अभियंता (सीसीई), उत्तर ने दो सप्ताह के भीतर स्थापना को सफलतापूर्वक पूरा किया। केंद्र में 500 बेड, 40 केएलडी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन गैस आपूर्ति प्रणाली, गहन देखभाल इकाइयाँ, वेंटिलेटर, एक प्रयोगशाला, एक औषधालय और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ सुसज्जित थीं। डीआरडीओ ने पूरे संचालन अवधि (5 मई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) के लिए संचालन को सुगम बनाया और चिकित्सा स्टाफ प्रदान किया। इस पहल के लिए लगभग पच्चीस करोड़ रुपये की कुल धनराशि को 60% पीएम केयर्स और 40% सीएसआर से जुटाया गया, जिसमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद और अन्य पीएसयू जैसे संगठनों से योगदान शामिल था। पीएमओ के निर्देश के बाद, डीआरडीओ ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) से वित्तीय सहायता मांगी। अपील के जवाब में, बीडीएल ने ₹ 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान डीआरडीओ को वितरित की। इस महत्वाकांक्षी उद्यम ने हजारों गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर चिकित्सा देखभाल और जीवन रक्षक उपचार प्रदान किया।

प्रभावशीलता: अस्थायी कोविड-19 अस्पताल की स्थापना के साथ उद्देश्य प्राप्त किया गया। डीआरडीओ के साथ कुशल सहयोग के माध्यम से, इस सुविधा पर बड़ी संख्या में कोविड मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया,



जिससे कई लोगों की जान बचाई गई। इस अस्थायी केंद्र की स्थापना के बाद, 5 मई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक हजारों गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल और जीवन रक्षक हस्तक्षेप प्रदान किए गए।

प्रभाव: लखनऊ में 500 बेड वाले अटल बिहारी वाजपेयी अस्थायी कोविड केयर सेंटर की स्थापना ने 5 मई, 2021 से दूसरी लहर के अंत तक कई कोविड-19 मरीजों को उपचार प्रदान किया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम हुआ। यह केंद्र तीसरी लहर की तैयारी में संभावित आपात स्थितियों को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद, कोविड-19 के बोझ को पूरी तरह से कम करने के बाद चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं अन्य स्वास्थ्य प्रणालियों को वैकल्पिक उपचारों के लिए हस्तांतरित कर दी गईं।

परियोजना 6: सिकंदराबाद के सैन्य अस्पताल और हैदराबाद के संनगर में ईएसआईसी अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की कमीशनिंग

अप्रैल और जुलाई 2021 में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान भारत में ऑक्सीजन आपूर्ति संकट का गंभीर प्रभाव पड़ा। देश भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कोविड-19 से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। संक्रमित मरीजों की भारी संख्या ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप बेड, ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी हुई। तेलंगाना राज्य ने दूसरी लहर के दौरान महत्वपूर्ण चुनौती का सामना किया, जिसमें उच्च संक्रमण और मृत्यु दर का अनुभव हुआ। सिकंदराबाद में सैन्य अस्पताल और हैदराबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तीव्र ऑक्सीजन की कमी को संबोधित करने के लिए, बीडीएल ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए, कोविड-19 उपचार के लिए निरंतर ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक की क्षमता 960 लीटर वाले ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की पहल की। ये स्थापनाएँ कोविड-19 की दूसरी लहर के अंत की ओर, जून 2021 से सितंबर 2021 तक, महामारी की तीसरी लहर और अन्य संभावित स्वास्थ्य संकटों की तैयारी में हुईं। बीडीएल ने दोनों अस्पतालों में इन दो ऑक्सीजन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए ₹ 188.80 लाख का व्यय किया।

परिणाम: यह परियोजना गंभीर देखभाल मरीजों का इलाज करने वाले ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और सिकंदराबाद के सैन्य अस्पताल को इष्टतम स्तर की ऑक्सीजन आपूर्ति के वांछित परिणामों को देने में सफल रही। इस परियोजना ने तेलंगाना राज्य में सैन्य अस्पताल और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चिकित्सा अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत किया। इसके अलावा, इस परियोजना ने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सक्षम की, जो इन अस्पतालों को किसी भी विनाशकारी स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना करने में मदद कर सकती है।

प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने हमारे स्वास्थ्य प्रणाली और इसके वितरण प्रोटोकॉल को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत किया है। ऑक्सीजन-उत्पादन संयंत्रों की स्थापना और ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणालियों जैसे चिकित्सा अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान ने तेलंगाना में सैन्य अस्पताल और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को सशस्त्र बलों के कर्मियों, ईएसआई-बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न मरीजों का समय पर इलाज करने में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का भारी बोझ ऑक्सीजन संयंत्रों द्वारा कम किया गया, जिसने अस्पतालों को 92-96% संतृप्ति ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए 5 से 15 LPM की दर से ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले गंभीर रूप से बीमार मरीजों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को प्रबंधित करने और बचाने की अनुमति दी।

परियोजना 7: हैदराबाद के संनगर में ईएसआईसी में कोविड पृथक्करण सुविधाओं की स्थापना

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (ईएसआईसी एमसी और एच), संनगर, हैदराबाद, एक 800 बेड का अस्पताल है जो तेलंगाना में ईएसआई योजना के तहत कवर किए गए 14 लाख से अधिक बीमाकृत व्यक्तियों की सेवा करता है। कोविड के दौरान इस अस्पताल ने कोविड और गैर-कोविड दोनों सेवाएँ प्रदान कीं। इस अस्पताल में प्रतिदिन 2400 से अधिक मरीजों का आना-जाना होता है। गैर-कोविड मरीजों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए जहाँ कोविड-19 मरीजों का इलाज किया जा रहा था, ईएसआईसी एमसी और एच ने परिसर में विभिन्न आठ रणनीतिक स्थानों पर फ्लैप बैरियर स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, उन्होंने कोविड-19 आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत बीडीएल से सीएसआर धन के लिए संपर्क किया, और परिणामस्वरूप, आठ फ्लैप बैरियर सफलतापूर्वक स्थापित किए गए। फ्लैप बैरियर ने मरीजों और मरीजों के परिचारकों के प्रवाह को कोविड और गैर-कोविड उपचार क्षेत्रों में कम करने में मदद की, जबकि केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई जो इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए अधिकृत थे। परियोजना की कुल लागत ₹ 170 लाख थी।

परिणाम: ईएसआईसी एमसी एंड एच ने रणनीतिक स्थानों पर 8 फ्लैप बैरियर लागू करके अनधिकृत व्यक्तियों या ईएसआईसी-बीमाकृत मरीजों के अत्यधिक परिचारकों के लिए पहुंच को नियंत्रित करने और कर्मचारी उपस्थिति की निगरानी के अपने परियोजना उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इन फ्लैप बैरियर को नियंत्रकों से जोड़ा गया है जो उनकी कनेक्टिविटी की लगातार निगरानी करते हैं और पहुंच के लिए उपयोग किए गए आरएफआईडी कार्ड से डेटा संचारित करते हैं। नियंत्रक आईटी सर्वर रूम में दो सर्वरों से जुड़े हैं, जो विश्लेषण के लिए आवश्यक पहुंच विवरण संग्रहीत करते हैं। इसके अतिरिक्त, एप्लिकेशन उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली के लिए बैकअप के रूप में कार्य करता है, जो फ्लैप बैरियर के लिए उपयोग किए गए उसी एप्लिकेशन द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर कर्मचारी उपस्थिति के लिए चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करता है।

प्रभाव: इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जैसे ईएसआईसी एमसी एंड एच में ईएसआईसी-बीमाकृत व्यक्तियों और उनके साथियों की पहुंच के लिए निगरानी प्रणालियों में सुधार, अनधिकृत प्रवेश की रोकथाम, और कर्मचारी समयबद्धता को बढ़ावा देना। इन संवर्द्धनों ने ईएसआईसी-बीमाकृत मरीजों के डेटा के बेहतर प्रबंधन, कर्मचारी दक्षता और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को अनुकूलित करके परिचालन लागत को कम करने में योगदान दिया। यह पहल विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान लाभकारी थी, क्योंकि इसने कार्ड पहुंच प्रणाली के माध्यम से केवल पात्र सामान्य और ईएसआईसी-बीमाकृत व्यक्तियों के लिए उपचार की अनुमति देकर कोविड-19 और गैर-कोविड-19 दोनों मरीजों के प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया, जिसके परिणामस्वरूप परिसर में व्यक्तियों के बीच वायरस संचरण में कमी आई।



अध्याय I

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी: एक अवलोकन

कंपनियां न केवल अपनी लाभप्रदता और वृद्धि पर ध्यान देती हैं, बल्कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की अवधारणा के माध्यम से समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए कल्याण और पर्यावरण गतिविधियों पर भी विचार करती हैं। सीएसआर को सामाजिक नीतियों, प्रथाओं और पहलों का एक व्यापक संग्रह माना जाता है जो व्यवसाय संचालन में एकीकृत होते हैं ताकि समाज की अपेक्षाओं और उनके व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) एक स्व-नियामक ढांचा है जो एक कंपनी को स्वयं, अपने हितधारकों और व्यापक समुदाय के प्रति जवाबदेही बनाए रखने में सक्षम बनाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में शामिल होकर, जिसे अक्सर कॉर्पोरेट नागरिकता कहा जाता है, संगठन अपने विभिन्न सामाजिक आयामों पर प्रभाव के प्रति सचेत हो सकते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक शामिल हैं। सीएसआर में समाज में सार्थक योगदान देना और कर्मचारियों, ग्राहकों, शेयरधारकों, आपूर्तिकर्ताओं और आम जनता जैसे हितधारकों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करके संतुलित विकास को बढ़ावा देना शामिल है। मूल रूप से, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में वे रणनीतियाँ शामिल होती हैं जो कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन को समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनाती हैं, जिसमें स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और संचालन में नैतिक प्रथाओं को संबोधित करना शामिल है।

समाज को वापस देना भारतीय संस्कृति और नैतिकता का एक मूलभूत घटक है, और पारंपरिक भारतीय उद्यमों ने शुरू से ही इस दृष्टिकोण को अपनाया है। हमारे पवित्र ग्रंथ समाज में योगदान देने के मूल्य पर जोर देते हैं। भारत की प्राचीन चेतना/सोच, जो आज भी मान्य है, व्यक्तियों को सभी हितधारकों की भलाई सुनिश्चित करने के अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय उद्योग का सामाजिक रूप से जागरूक होने का इतिहास रहा है, और कुछ प्रमुख कंपनियों ने इस क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किए हैं।

कई वर्षों से विधायिका ने विभिन्न सामाजिक, श्रम और पर्यावरणीय कानून पारित किए हैं ताकि व्यवसायों को अपने कर्मचारियों, पड़ोसियों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिल सके। अधिनियम में सीएसआर उपायों को शामिल करना एक अभूतपूर्व विधायी पहल है ताकि निगमों को राष्ट्र के सामाजिक विकास प्रक्रिया में हितधारक के रूप में शामिल किया जा सके और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत किया जा सके।

कंपनी अधिनियम 2013 एक ऐसा विधान है जिसने सीएसआर को अनिवार्य बनाने में दुनिया के सबसे बड़े प्रयोगों में से एक की शुरुआत की। सीएसआर सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी विचार है। सरकार सीएसआर को शामिल करके व्यवसायों को राष्ट्रीय विकास के एजेंडे में शामिल करने की कोशिश करती है। अधिनियम में सीएसआर प्रावधानों को शामिल करने के साथ, निगमों पर अब सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय

प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाने की कानूनी जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 135 और इसके द्वारा बनाए गए सीएसआर नियम भारत में सीएसआर के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 ने 2014 में सीएसआर को अनिवार्य किया। तब से, भारत में सीएसआर के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कई संशोधन और बदलाव पेश किए गए हैं। सीएसआर पहल का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारत को नया रूप देना है। हालांकि कई कॉर्पोरेट और औद्योगिक संगठनों द्वारा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से ऐसा किया जाता रहा है, सीएसआर उन कंपनियों के लिए अनिवार्य हो गया है जो मानदंडों में आती हैं और कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दी गई गतिविधियों को शुरू करें।



अध्याय II

भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इसकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को 16 जुलाई, 1970 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इस उपक्रम के गठन का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ज़रूरी मिसाइल प्रणालियों और संबद्ध उपकरणों के विनिर्माण हेतु एक ठोस आधार तैयार करना था।

अपनी स्थापना के बाद से, बीडीएल डीआरडीओ और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ मिलकर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न मिसाइलों और संबद्ध उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए काम कर रही है। राष्ट्र द्वारा स्वदेशी, परिष्कृत और समकालीन मिसाइलों को विकसित करने के लिए शुरू की गई एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) ने बीडीएल को इस कार्यक्रम में निकटता से शामिल होने का अवसर दिया, जिसमें इसे प्राथमिक उत्पादन एजेंसी के रूप में पहचाना गया। इससे उन्नत विनिर्माण और कार्यक्रम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों और कौशलों को आत्मसात करने के लिए ढेर सारे अवसर खुले। आज, बीडीएल दुनिया के उन कुछ उद्योगों में से एक के रूप में विकसित हुई है जिनके पास भारतीय सशस्त्र बलों के लिए निर्देशित मिसाइलों, जल के नीचे हथियारों, हवाई उत्पादों और संबद्ध रक्षा उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। कंपनी उत्पाद जीवन चक्र समर्थन और पुरानी मिसाइलों के नवीनीकरण / जीवन विस्तार की भी पेशकश करती है।

बीडीएल में सीएसआर

भारत डायनामिक्स लिमिटेड समाज की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को हल करने पर ध्यान देती है। बीडीएल की सीएसआर पहल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित (aligned) हैं और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाती हैं। कंपनी स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है, साथ ही स्थानीय क्षेत्रों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखती है।

सीएसआर गतिविधियों के क्षेत्र

कंपनियों द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीतियों में शामिल की जा सकने वाली गतिविधियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं:

- (i) भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना जिसमें निवारक स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता शामिल है, जिसमें स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

- (ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अलग-अलग सक्षम लोगों के बीच, और आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ।
- (iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।
- (iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पति और जीव-जंतुओं की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के पुनर्जनन के लिए स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान शामिल है।
- (v) राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की सुरक्षा, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों और कलाकृतियों का पुनरुद्धार शामिल है; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास।
- (vi) सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के सेवानिवृत्त और उनके आश्रितों सहित विधवाओं के लाभ के उपाय।
- (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।
- (viii) प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।
- (ix) A. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर्स या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान।
 B. सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों में योगदान।
 - ग्रामीण विकास परियोजनाएँ।
 - झुग्गी क्षेत्र विकास।
 - आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

बीडीएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बोर्ड स्तर से नीचे सीएसआर और एसडी समिति, बोर्ड स्तर पर सीएसआर और एसडी समिति का गठन किया है।



अध्याय III

अनुसंधान पद्धति और दृष्टिकोण

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का उद्देश्य परियोजनाओं के परिणामों और प्रभाव को निर्धारित करना है। आईपीई वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए 03 सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ओईसीडी डीएसी नेटवर्क ऑन डेवलपमेंट इवैल्यूएशन ढांचे को अपनाता है और प्रत्येक सीएसआर परियोजना का बजट एक करोड़ से ऊपर था। प्रभाव के मानदंड चयनित परियोजना की प्रासंगिकता, दक्षता, प्रभावशीलता, प्रभाव, स्थिरता और सुसंगतता का अध्ययन करना है। ये मानदंड एक नियामक ढांचा प्रदान करते हैं जिसका उपयोग किसी हस्तक्षेप (नीति, रणनीति, कार्यक्रम आदि) की योग्यता या मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है।



Source: OECD DAC Framework

अध्ययन संबंधित पद्धति का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजेगा:

- सीएसआर परियोजना के इच्छित/योजनाबद्ध परिणाम क्या हैं?
- किन समूहों को परिवर्तनों से प्रभावित (या अप्रभावित) किया गया है?
- परियोजना को लागू करने की विधि क्या है और कार्यान्वयन एजेंसी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यदि कोई हो?
- परियोजना हितधारकों की मांगों/अपेक्षाओं को पूरा करने में कितनी महत्वपूर्ण है?
- क्या परियोजना में स्थिरता है या नहीं?

अध्ययन का दायरा: अध्ययन का दायरा निम्नलिखित को शामिल करता है:

- मौजूदा परियोजना दस्तावेजों की समीक्षा जैसे परियोजना समझौता दस्तावेज, आधारभूत अध्ययन रिपोर्ट, यदि कोई हो, परियोजना प्रगति रिपोर्ट, पूर्णता रिपोर्ट।
- परियोजनाओं की सूची से नमूना चयन और हितधारक संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण करना।
- प्रभाव से संबंधित परियोजना परिणामों का विश्लेषण और सारांश करना।
- अंतराल की पहचान करना और सिफारिशें तैयार करना।

विस्तृत अनुसंधान पद्धति


प्रभाव अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए चार-चरण संरचित को अपनाता है। कार्यक्रमों के प्रभावों का सटीक आकलन करने के लिए, अपनाई गई पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि ओईसीडी डीएसी मूल्यांकन मानकों का पालन किया जाए।



अध्याय IV

परियोजनावार विश्लेषण

परियोजना 1: विजयनगरम के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम

परियोजना का नाम	विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम
परियोजना लागत	100 लाख
निष्पादन अवधि	2021-22
सीएसआर विषयगत क्षेत्र	शिक्षा को बढ़ावा देना (अनुसूची VII, धारा 135, मद सं. 2)
एसडीजी लक्ष्य	
परियोजना का उद्देश्य	परियोजना का उद्देश्य विजयनगरम जिले के चयनित सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षा प्रणाली प्रदान करके सरकारी स्कूलों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
कुल लाभार्थी	2500 स्कूली बच्चे

परियोजना की पृष्ठभूमि

पारंपरिक कक्षाओं में आमतौर पर एकतरफा संप्रेषण रहता है, जहाँ शिक्षक व्याख्यान देते हैं और छात्र नोट्स लेते हैं। दूसरी ओर, स्मार्ट क्लास रूम मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड और शैक्षिक ऐप से लैस हैं ताकि विद्यार्थियों की समझ बढ़ाई जा सके। स्मार्ट कक्षाओं में दृश्य और इंटरैक्टिव तत्वों को शामिल करने से न केवल जुड़ाव बढ़ता है बल्कि अकादमिक प्रदर्शन भी बढ़ता है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों ने पारंपरिक कक्षाओं की तुलना में इस डिजिटल क्लास रूम अवधारणा 20% बेहतर अवधारण का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट क्लासरूम डिजिटल लाइब्रेरी, ई-बुक्स और ऑनलाइन शोध सामग्री तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों का ज्ञान समृद्ध होता है।

विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण और सीखने का माहौल विकसित करने के उद्देश्य से, जन प्रतिनिधियों, जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न हितैशियों ने स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम लागू करने के लिए सीएसआर निधि सुरक्षित करने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बीडीएल ने विजयनगरम जिले के 34 प्राथमिक और 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40 स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम स्थापित करने के लिए 100 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी।

परियोजना की पहल

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बीडीएल ने विजयनगरम जिले के कुछ चुने हुए सरकारी स्कूलों में 40 के-यान स्मार्ट क्लासरूम सफलतापूर्वक स्थापित किए, जिसमें आरईएस टेक्नोलॉजी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। परियोजना की कुल लागत 100 लाख रुपये थी, जिससे कुल 2500 छात्र लाभान्वित हुए। स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड ने इस पहल में तकनीकी भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मंडलवार कुल संख्या

क्रम संख्या	मंडल का नाम	स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम इंस्टालेशन के लिए मंडलवार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नंबर		
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	कुल
1	डेन्कडा	02	01	03
2	पुसापतिरेगा	04	02	06
3	भोगापुरम	04	00	04
4	विजयनगरम	04	02	06
5	मेराका मुदिदम	02	00	02
6	चिपुरपल्ली	04	00	04
7	गैरीविडी	02	00	02
8	गुरला	05	00	05
9	नेल्लीमारला	06	00	06
10	गण्ट्यादा	01	01	02
	कुल	34	06	40

के-यान स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम के बारे में



के-यान स्मार्ट क्लासरूम – विभिन्न घटक

के-यान एक एकीकृत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समाधान है जो सामग्री प्रस्तुति की सुविधा प्रदान करता है, एनोटेशन कार्यों का समर्थन करता है, और एक सुखद और इंटरैक्टिव तरीके से सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ऑल-इन-वन डिवाइस विभिन्न तकनीकों को एक इकाई में जोड़ता है, जैसा कि उपरोक्त आरेख में दिखाया गया है। के-यान स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम इंटेल आई 3 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम, एक उन्नत प्रोजेक्शन सिस्टम, इन-बिल्ट इंटरैक्टिव बोर्ड और ऑडियो सिस्टम और एक डीवीडी प्लेयर के साथ बनाया गया है। के-यान एक कंप्यूटर, एक प्रोजेक्टर, उच्च चमक प्रोजेक्टर, इन-बिल्ट स्पीकर, एक 500 जीबी एचडीडी, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक वायरलेस कीबोर्ड, एक माउस और अधिक की कार्यक्षमता को एक एकल इंटरैक्टिव डिवाइस में जोड़ती है।



बीडीएल ने विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में केवाईएन के-यान स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम स्थापित किया

प्रभाव विश्लेषण ढांचा: इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन के लिए विभिन्न मापदंडों के ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष निम्नवत् है:

प्रासंगिकता: विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम निर्देश का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो कक्षा शिक्षण में डिजिटल परिवर्तन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रयासों और भारत सरकार की समग्र शिक्षा परियोजना के साथ संरेखित होती है। ये सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण और सीखने की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक पहल है। यह परियोजना नई शिक्षा नीति 2020 का भी समर्थन करती है।

दक्षता: यह पहल निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए और निधियों के उचित आबंटन के साथ एक व्यवस्थित, चरणबद्ध तरीके से की गई है। स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम का शिक्षकों और छात्रों दोनों द्वारा बेहतर उपयोग किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक विभिन्न विषयों की छात्रों की समझ को बढ़ाने के लिए प्रीलोडेड विषय सामग्री, ई-पुस्तकें, वीडियो व्याख्यान, इंटरैक्टिव लर्निंग संसाधन और यूट्यूब से डाउनलोड किए गए पाठ जैसी डिजिटल सामग्री की एक विविध श्रेणी का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों के पास डिजिटल संसाधनों और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच है। इंटरनेट कनेक्टिविटी छात्रों को पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों से परे जानकारी में तल्लीन करने में सक्षम बनाती है, जिससे विभिन्न विषयों की उनकी समझ में सुधार होता है। नतीजतन, छात्र विषय वस्तु को अधिक आसानी से समझ सकते हैं और अपने शैक्षणिक आकलन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रभावशीलता: बीडीएल ने विजयनगरम जिले के चयनित 40 सरकारी स्कूलों में 40 केवाईएन स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम स्थापित करके परियोजना के उद्देश्य को हासिल किया। इस परियोजना से कुल 2500 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र लाभान्वित हुए, जो विविध विषय सामग्रियों से जुड़ते हैं और प्रतिदिन स्मार्ट कक्षा सत्रों में भाग लेते हैं। नतीजतन, स्कूलों ने प्रति दिन 3-4 स्मार्ट कक्षा सत्र आयोजित किए, जो छात्रों को समृद्ध शैक्षिक अनुभव प्रदान करते हैं

और इसके परिणामस्वरूप उनके मौलिक संख्यात्मक कौशल, पर्यावरण विज्ञान अवधारणाओं की समझ के साथ-साथ अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में दक्षता में वृद्धि होती है।

परिणाम

- तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में स्कूली बच्चों के बीच बेहतर एल एस आर डब्ल्यू (लिजन, स्पीकिंग, रीडिंग अण्ड राइटिंग) कौशल
- स्कूली बच्चों के बीच बुनियादी संख्यात्मक कौशल और बुनियादी गणितीय विषयों में सुधार।
- स्कूली बच्चों के बीच प्रकृति, पर्यावरण, शरीर के हिस्सों, अच्छी भोजन की आदतों, परिवहन के साधन, परिवार और अन्य जैसे विभिन्न पर्यावरणीय अवधारणाओं की समझ में सुधार हुआ।
- स्कूली बच्चों के बीच संबंधित अवलोकन कौशल।
- शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि में वृद्धि।

प्रभाव: इन स्कूलों के अधिकांश छात्र कृषि, श्रम-गहन कार्य, जाति से संबंधित व्यवसायों, छोटे व्यवसायों या निजी क्षेत्र में लगे परिवारों से हैं। इससे पहले सरकारी स्कूलों में शैक्षिक मानकों की कमी ने तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में बुनियादी पढ़ने और लिखने के कौशल के साथ-साथ नंबरिंग सिस्टम, टेबल, सरल गणित गणना और बुनियादी पर्यावरणीय अवधारणाओं के मौलिक ज्ञान हासिल करने की उनकी क्षमता में बाधा डाली थी। इसके अलावा, उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को स्मार्ट कक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन से पहले गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषाओं जैसे विषयों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ़ा संप्रेषण के साथ पारंपरिक कक्षा शिक्षण अक्सर छात्र ऊब जाते थे और विभिन्न लाइव अनुभव ऑडियो-वीडियो दृश्यों के बिना कक्षा में मन नहीं लगता था। हालांकि, इस परियोजना ने कक्षा शिक्षण और सीखने के वातावरण को बदल दिया है, जिससे शैक्षिक मानकों में सुधार हुआ है, स्कूल नामांकन में भी वृद्धि हुई है, अनुपस्थिति कम हुई है और सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि देखने में आई है।

सम्बद्धता: यह परियोजना तेलंगाना सरकार और भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही स्कूली शिक्षा पर विभिन्न नीतियों के अनुसार है।

स्थिरता: परियोजना के परिणामों का स्थायी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राप्तकर्ता स्कूलों को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही शिक्षा विभाग, स्कूल विकास और प्रबंधन समिति और संबंधित स्थानीय निकाय से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से सभी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परिणामस्वरूप, परियोजना सफल हुई।

परियोजना का प्रदर्शन

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर
प्रासंगिकता	अति उत्कृष्ट	18
दक्षता	अति उत्कृष्ट	17
प्रभावशीलता	अति उत्कृष्ट	17
प्रभाव	अति उत्कृष्ट	17
स्थिरता	अति उत्कृष्ट	17
कुल स्कोर	अति उत्कृष्ट	86



व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत खराब: 1 to 4

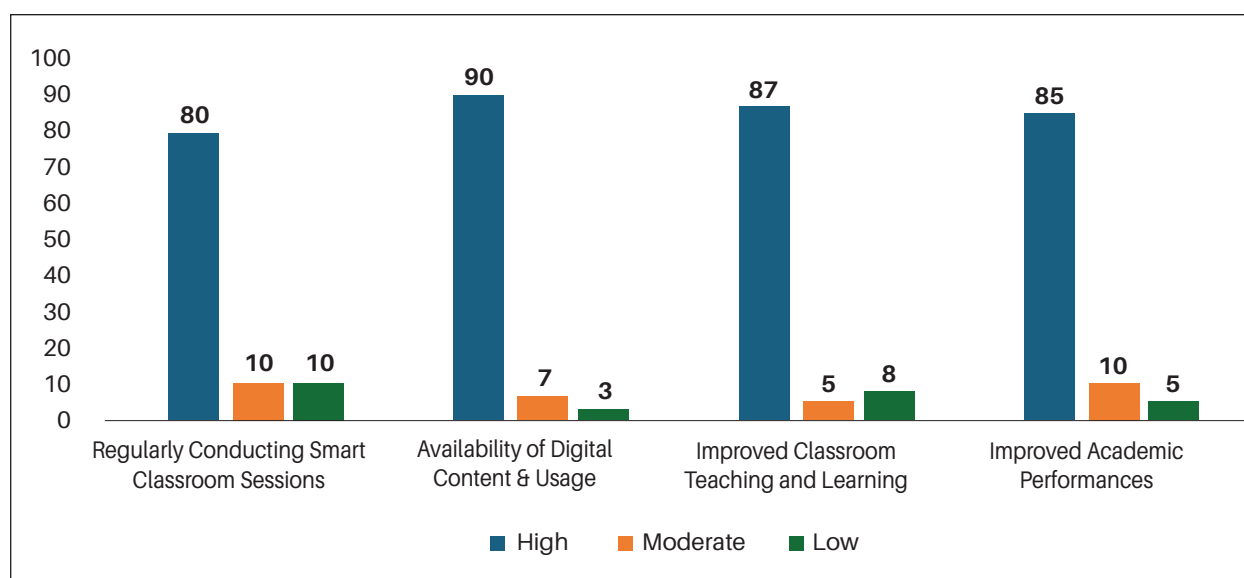
कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत खराब (1 to 20)

संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

हितधारक सर्वेक्षण विवरण

क्रम संख्या	आईपीई टीम ने स्कूल के नाम का दौरा किया	कुल संख्या	प्रश्नावली भरने के लिए चयन कक्षाएं	प्रश्नावली की कुल संख्या
1	एमपीपीएस दुप्पदा (I से V)	79 (लड़के: 39 और लड़कियां: 40)	IV और V	30 (लड़के: 15 और लड़कियां: 15)
2	एमपीयूपीएस सिंगावरम (I से VIII)	72 (लड़के: 45 और लड़कियां: 27)	IV और V	30 (लड़के: 15 और लड़कियां: 15)
3	एमपीपीएस रामावरम	29 (लड़के: 14 और लड़कियां: 15)	-	-
4	एमपीपीएस पुसापतिरेगा	23 (लड़के: 10 और लड़कियां: 13)	-	-

अ) छात्र: आईपीई टीम ने परियोजना पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एमपीपीएस-डुप्पाड़ा और एमपीयूपीएस-सिंगवरम में चौथी और पांचवीं कक्षाओं के 30 लड़के और 30 लड़कियों के बराबर विभाजन के साथ 60 छात्रों को एक संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण प्रश्नावली वितरित की। 80% छात्रों ने अपनी कक्षाओं में आयोजित नियमित स्मार्ट कक्षा सत्रों के साथ उच्च संतुष्टि व्यक्त की। अधिकांश छात्रों ने कहा कि दोनों स्कूल विभिन्न कक्षाओं के लिए प्रतिदिन 4 स्मार्ट कक्षा सत्र आयोजित करते हैं, जो मुख्य रूप से पर्यावरण विज्ञान अवधारणाओं, बुनियादी गणित अवधारणाओं, बुनियादी तेलुगु एल एस आर डब्ल्यू कौशल और मानव-मूल्य पर आधारित कहानियों पर केंद्रित हैं। उत्तरदाताओं के 90% ने कक्षा शिक्षण और छात्र सीखने में डिजिटल सामग्री की उपलब्धता और उपयोग के साथ अपनी उच्च संतुष्टि प्रकट की।



छात्रों को अपने सीखने के माहौल में विभिन्न डाउनलोड की गई विषय सामग्री, व्याख्यान, ई-पुस्तकें और प्रीलोडेड विषय सामग्री तक पहुंच प्राप्त है। उन्होंने अनुरोध किया कि स्कूल के अधिकारी नियमित पाठ्यक्रम में हो रहे बदलाव के साथ संरेखित करने के लिए समय-समय पर विषय सामग्री को अपडेट करें। 87% छात्रों ने शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए स्मार्ट कक्षा निर्देश के कारण बेहतर कक्षा शिक्षण और सीखने के माहौल के साथ उच्च संतुष्टि व्यक्त की। छात्रों ने जोर दिया कि शिक्षक ऑडियो-विजुअल एड्स, ग्राफिक्स, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, डाउनलोड की गई सामग्री जैसे विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें विषय विषयों के साथ एकीकृत करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक बढ़िया कक्षा शिक्षण और सीखने का माहौल होता है। 85% उत्तरदाताओं ने स्मार्ट कक्षा प्रणालियों के साथ कक्षा शिक्षण और सीखने में बदलते पैटर्न के कारण अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के साथ उच्च संतुष्टि व्यक्त की।

ब) शिक्षक: आईपीई टीम ने चार सरकारी स्कूलों के 08 शिक्षकों के साथ बातचीत की, जिनमें से सभी ने स्मार्ट कक्षाओं द्वारा सुगम आधुनिक कक्षा शिक्षण और सीखने के माहौल में सुधार के साथ अपनी उच्च संतुष्टि व्यक्त की। शिक्षकों ने स्मार्ट प्रोजेक्टर का उपयोग करके अपने आधुनिक शिक्षण कौशल को बढ़ाने के अवसर की सराहना की, जिससे वे छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन करने और प्रभावी पाठ योजना बनाने में सक्षम हुए। इस परियोजना ने न केवल छात्र प्रगति का आकलन करने की उनकी क्षमता में सुधार किया बल्कि उन्हें पाठों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षकों ने पेशेवर रूप से प्रशिक्षित महसूस किया और स्मार्ट कक्षाएं आयोजित करने के लिए तैयार महसूस किया, हाइब्रिड शिक्षण विधियों की खोज में रुचि दिखाई।

स) अभिभावक: आईपीई टीम ने चार स्कूलों के बारह अभिभावकों के साथ बातचीत की, जिनमें से सभी ने बीडीएल द्वारा स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के बाद सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के कार्यान्वयन के साथ अपनी उच्च संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने अपने स्कूलों में इन स्मार्ट कक्षाओं की आपूर्ति के लिए बीडीएल की सराहना की और कक्षा निर्देश और सीखने के माहौल में सुधार को माना, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा के मानकों में बेहतरी आई।

समग्र अवलोकन

- सभी शैक्षणिक संस्थानों ने स्मार्ट कक्षाओं की सफल स्थापना और वारंटी अवधि के दौरान सामने आए स्मार्ट कक्षा प्रणालियों के मुद्दों के समय पर समाधान की सूचना दी है। हालांकि, वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद स्कूलों के एक छोटे प्रतिशत को हार्डवेयर या सिस्टम समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- डिजिटल लर्निंग पहल ने शिक्षकों और छात्रों दोनों से महत्वपूर्ण भागीदारी प्राप्त की है। गणित और विज्ञान ने उपयोग दरों को 70% से अधिक दिखाया है, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है।
- स्कूल आमतौर पर साप्ताहिक रूप से 20-24 स्मार्ट कक्षा सत्र आयोजित करते हैं।
- डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के लाभों में नई अवधारणाओं की सरलीकृत व्याख्या, छात्र जुड़ाव में वृद्धि, आधुनिक शिक्षण विधियों और कम प्रशिक्षकों के साथ कुशल प्रबंधन शामिल हैं।
- विभिन्न विषयों के लिए प्रीलोडेड सामग्री आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ संरेखित होती है।
- कुछ स्कूल छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निदानात्मक कक्षाओं (रेमेडी क्लासेस) के लिए स्मार्ट कक्षाओं का उपयोग करते हैं।



केस स्टडी

केस स्टडी 1

“हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम लागू होने से पहले, गणित मेरे लिए बहुत जटिल था। बहुत तकलीफ उठाता था।, विशेष रूप से नंबरिंग सिस्टम, बुनियादी अंकगणितीय संचालन और अंशों जैसे क्षेत्रों में। हालांकि, इस तकनीक की शुरुआत ने मेरे सीखने के अनुभव में क्रांति ला दी। इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों, दृश्य उपकरण और चरण-दर-चरण समस्या-समाधान वीडियो के माध्यम से, मैं बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सक्षम था। इससे न केवल मुझे अपने विश्लेषणात्मक और तर्क कौशल में सुधार करने में मदद मिली, बल्कि चौथी कक्षा की अंतिम परीक्षा में मेरे गणित विषय के प्रदर्शन में 40% से 90% तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हमें यह अमूल्य संसाधन प्रदान करने के लिए मैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड का आभारी हूँ।

पी. धनुष

वी मानक, एमपीपीएस - दुप्पड़ा

केस स्टडी 2

“के-यान स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम एक व्यापक उपकरण है जो कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव बोर्ड और ऑडियो सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के सहज एकीकरण के माध्यम से शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदल देता है। एनिमेटेड चित्रों, ग्राफिक्स और वीडियो सहित आकर्षक ऑडियो-विजुअल सामग्री का समावेश, न केवल छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है बल्कि विभिन्न विषयों की उनकी समझ को भी बढ़ाता है। स्मार्ट क्लास सत्रों की इंटरैक्टिव प्रकृति बच्चों को गणितीय अवधारणाओं और पर्यावरण अध्ययन जैसे जटिल विषयों को सक्रिय रूप से भाग लेने और समझने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा, कक्षा निर्देश में मल्टीमीडिया उपकरणों के उपयोग ने स्कूली बच्चों में शिक्षाविदों के प्रति गहरी रुचि पैदा की है, जिससे अनुपस्थिति और ड्रॉपआउट में उल्लेखनीय कमी आई है, जबकि छात्रों के तकनीकी कौशल और डिजिटल सीखने के साथ समग्र आराम भी बढ़ा है”।

श्री इजराइल राजू

हेडमास्टर, एमपीयूपीएस - सिंगावरम

परियोजना 2: राजन्ना सिरसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण

परियोजना का नाम	राजन्ना-सिरसिला जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के शौचालयों का निर्माण
परियोजना लागत	200 लाख
निष्पादन अवधि	2020-21 और 2021-22
सीएसआर विषयगत क्षेत्र	स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर 1) शिक्षा को बढ़ावा देना (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर 2)
एसडीजी लक्ष्य	   
परियोजना का उद्देश्य	परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ विद्यालय मिशन के हिस्से के रूप में राजन्ना-सिरसिला जिले में चयनित सरकारी स्कूलों में खुले में शौच को खत्म करने के लिए छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण करना है।
कुल लाभार्थी	1400 स्कूली बच्चे – प्राथमिक विद्यालय के बच्चे: I to V कक्षा 200 स्कूली बच्चे – उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे: I to VII 1400 स्कूली बच्चे – हाई स्कूल के बच्चे: VI to X

परियोजना की पृष्ठभूमि

राजन्ना-सिरसिला जिले में छात्राओं की उपस्थिति में गिरावट और सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट में वृद्धि के मुख्य कारण लड़कियों के शौचालय थे। लड़कियों की उपस्थिति के स्तर और ड्रॉपआउट दरों के लिए इस महत्वपूर्ण बाधा को खत्म करने के लिए स्कूलों में उपयुक्त, छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। लिंग मानदंड और शारीरिक अंतर लड़कियों के लिए गोपनीयता के महत्व को उजागर करते हैं, विशेष रूप से मासिक धर्म की जैविक वास्तविकताओं को देखते हुए। इसलिए, पर्याप्त टॉयलेट सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सरकारी स्कूलों में लड़कियों की शौचालय सुविधाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट और राजन्ना-सिरसिला जिले के शिक्षा विभाग ने सक्रिय रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) से सीएसआर निधियों से आर्थिक सहयोग देने का अनुरोध किया गया। उनके प्रयास फलदायी रहे क्योंकि उन्हें वित्त पोषण में 200 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 39 चयनित सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों के निर्माण के लिए किया गया था। इन शौचालयों का निर्माण बीडीएल से उदार वित्तीय सहायता के कारण ही संभव हो पाया था। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू हुई और 2021-22 तक पूरी हुई।

परियोजना की पहल

चरणवार परियोजना विवरण इस प्रकार हैं:

परियोजना विवरण

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
स्कूलों की संख्या	18	21
शौचालय ब्लॉकों की संख्या	32	32



विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
प्रत्येक शौचालय ब्लॉक की लागत	Rs 3.10 लाख	Rs 3.10 लाख
शौचालय ब्लॉकों की लागत	Rs 99.20 लाख	Rs 99.20 लाख
अन्य व्यय	Rs 0.80 लाख	Rs 0.80 लाख
शौचालय निर्माण के लिए कवर किए गए स्कूलों की कुल संख्या	प्राथमिक स्कूल: 07 जेडपीएचएस उच्च विद्यालय: 11	प्राथमिक स्कूल: 15; मिडिल स्कूल: 03; जेडपीएचएस उच्च विद्यालय: 03
लाभार्थी	1400 (लगभग)	1600 (लगभग)

मंडल वार - राजना-सिरसिला जिले के सरकारी स्कूलों में निर्मित शौचालयों की कुल संख्या

क्रम संख्या	मंडल का नाम	प्राथमिक स्कूल		मिडिल स्कूल (यूपीएस)		उच्च विद्यालय (जेडपीएचएस)	
		कुल स्कूल	इकाइयां	कुल स्कूल	इकाइयां	कुल स्कूल	इकाइयां
	चरण I						
1	गंभीररावपेट	01	02	-	-	04	07
2	मुस्तबाद	-	-	-	-	02	06
3	सिरसिला	01	01	-	-	03	06
4	थंगालापल्ली	02	03	-	-	-	-
5	वीरनपल्ली	03	03	-	-	-	-
6	येल्लारेड्डीपेट	-	-	-	-	02	04
	उप-योग I	07	09	-	-	11	23
	चरण II						
1	गंभीररावपेट	03	05	-	-	01	02
2	मुस्तबाद	02	02	-	-	01	02
3	सिरसिला	04	05	01	02	-	-
4	थंगालापल्ली	01	02	-	-	01	02
5	वीरनपल्ली	03	04	-	-	-	-
6	येल्लारेड्डीपेट	02	04	02	02	-	-
	उप-योग II	15	22	03	04	03	06
	कुल योग (उप-योग I + उप-योग II)	22	31	03	04	14	29



प्रभाव विश्लेषण ढांचा: आईपीई टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के ओ ई सी डी डी ए सी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं।

प्रासंगिकता: इस प्रयास का महत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो सरकारी स्कूलों में परिचालन शौचालय सुविधाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा, यह समग्र शिक्षा, स्वच्छ विद्यालय अभियान और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुरूप है, जिनमें से सभी सरकारी स्कूलों में स्कूली बच्चों के लिए अलग शौचालय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने राजन्ना-सिरसिला जिले के 39 सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा प्रदान की है।

दक्षता: निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना के सफल समापन और बजट की कमी ने शौचालय डिजाइन, निर्माण मानकों, जल प्रावधान और आवश्यक सुविधाओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने को रेखांकित किया। राजन्ना-सिरसिला जिले के चयनित सरकारी स्कूलों में बीडीएल द्वारा निर्मित शौचालय अच्छी स्थिति में हैं और स्कूली बच्चों द्वारा उपयोग की उच्च दर भी है।

प्रभावशीलता: इस परियोजना का उद्देश्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है क्योंकि इसने राजन्ना-सिरसिला जिले में स्थित 39 सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए शौचालय सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया है। नतीजतन, सरकारी स्कूलों में उपलब्ध शौचालय सुविधाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कुल 3000 स्कूली बच्चे प्रतिदिन शौचालय सुविधाओं का उपयोग करते हैं।



प्रभाव

राजन्ना-सिरसिला जिले के सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों के निर्माण से महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति दर में सुधार और ड्रॉपआउट दर में कमी शामिल है। इस लाभकारी प्रभाव का श्रेय स्कूली बच्चों के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित अलग टॉयलेट की उपलब्धता को दिया जाता है, जो उनके बीच गरिमा और गोपनीयता की भावना को बढ़ावा देता है। नतीजतन, स्कूली बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना ने युवा छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ाया है।

सम्बद्धता: यह परियोजना तेलंगाना सरकार और भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही स्कूली शिक्षा संबंधी विभिन्न नीतियों के अनुसार है।

परिणाम: इस प्रयास के परिणामस्वरूप, राजन्ना-सिरसिला जिले के 39 सरकारी स्कूलों में 64 शौचालय ब्लॉक स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक शौचालय ब्लॉक में पांच स्क्वाटिंग-प्रकार के मूत्रालय और दो आईडब्ल्यूसी शौचालय हैं, जिनमें हाथ धोने के बेसिन, नल, बहते पानी की व्यवस्था आदि शामिल हैं। इन सभी सुविधाओं ने सरकारी स्कूलों में शौचालय सुविधाओं में काफी सुधार किया है, छात्राओं के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण बनाया है और उन्हें बीमारियों और सामाजिक बहिष्कार से बचाया है।

स्थिरता: इस परियोजना ने लंबे समय तक चलने वाले परिणाम प्राप्त किए हैं, जैसा कि कई स्कूलों में सफाई कर्मियों के रोजगार और टॉयलेट सुविधाओं को बनाए रखने में उनकी ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान की गई सहायता से पता चलता है। वर्तमान में, स्कूल इन सुविधाओं के रखरखाव के लिए पर्याप्त धन आवंटित कर रहे हैं।

परियोजना का प्रदर्शन

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर
प्रासंगिकता	औसत से ऊपर	17
दक्षता	औसत से ऊपर	15
प्रभावशीलता	औसत से ऊपर	15
प्रभाव	औसत से ऊपर	15
स्थिरता	औसत से ऊपर	15
कुल स्कोर	औसत से ऊपर	77



व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत खराब: 1 to 4

कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत खराब (1 to 20)

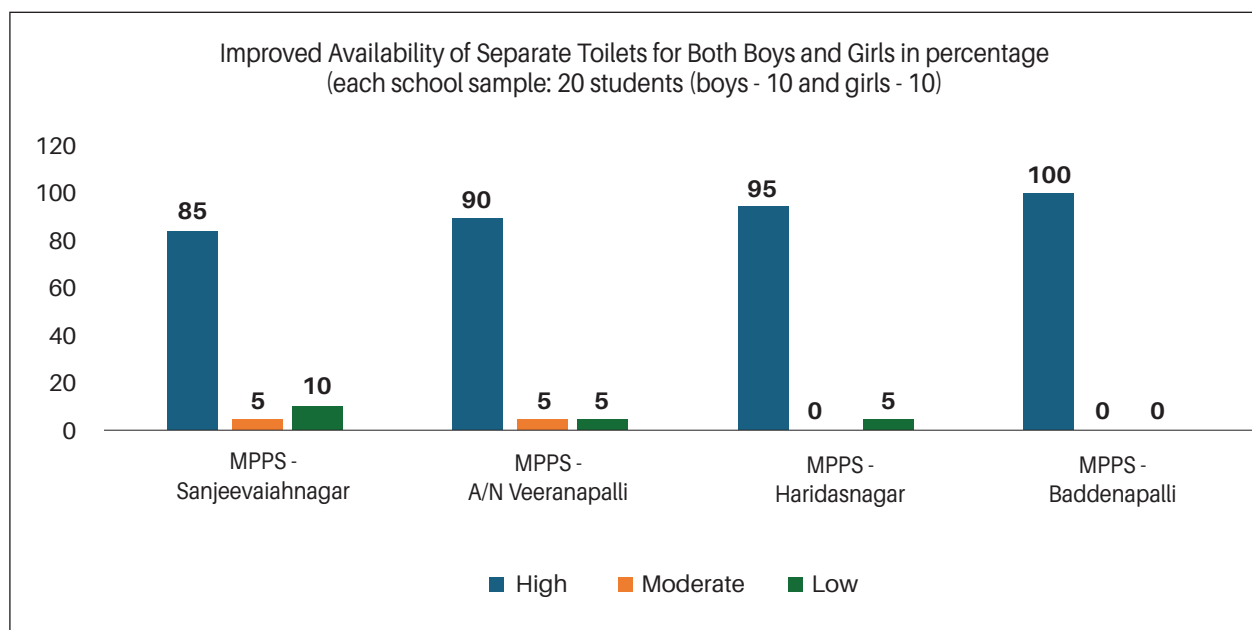
छात्र संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

आईपीई टीम ने राजन्ना-सिरसिला जिले के 4 सरकारी स्कूलों का दौरा किया, ताकि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों जैसे हितधारकों के संतुष्टि स्तर का आकलन किया जा सके, जिसमें स्कूल शौचालयों की गुणवत्ता, स्कूल शौचालयों की कार्यक्षमता, स्कूल शौचालयों की उपलब्धता में वृद्धि, शौचालयों में बहते पानी की उपलब्धता, स्कूल शौचालयों का नियमित रखरखाव, सरकारी स्कूलों में अच्छी स्वच्छता प्रथाओं पर जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित संचालन, और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के बाद परियोजना में समग्र सुधार। टीम ने प्रत्येक स्कूल से 20 छात्रों को शामिल किया, जिससे लड़कियों और लड़कों दोनों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। इन छात्रों से परियोजना के परिणामों और इन शौचालयों के उपयोग के संबंध में संतुष्टि के स्तर के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। प्रति स्कूल नमूने का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	स्कूल का नाम	कुल संख्या	बीडीएल द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या	कुल नमूना आकार और नमूना संरचना
1	एमपीपीएस संजीवय्या नगर	39 (लड़के: 24 और लड़किया : 15)	02 units (1 लड़का और 1 लड़की)	20 (10 लड़के और 10 लड़किया)
2	एमपीपीएस-ए/एन वीरनपल्ली	28 (लड़के: 12 और लड़किया: 16)	02 (1 लड़का और 1 लड़की)	20 (10 लड़के और 10 लड़किया)
3	एमपीपीएस-हरिदासनगर	57 (लड़के: 27 और लड़किया: 30)	02 (1 लड़का और 1 लड़की)	20 (10 लड़के और 10 लड़किया)
4	एमपीपीएस-बड्डेनापल्ली	92 (लड़के: 50 और लड़किया: 42)	02 (1 लड़का और 1 लड़की)	20 (10 लड़के और 10 लड़किया)

छात्र संतुष्टि स्तर

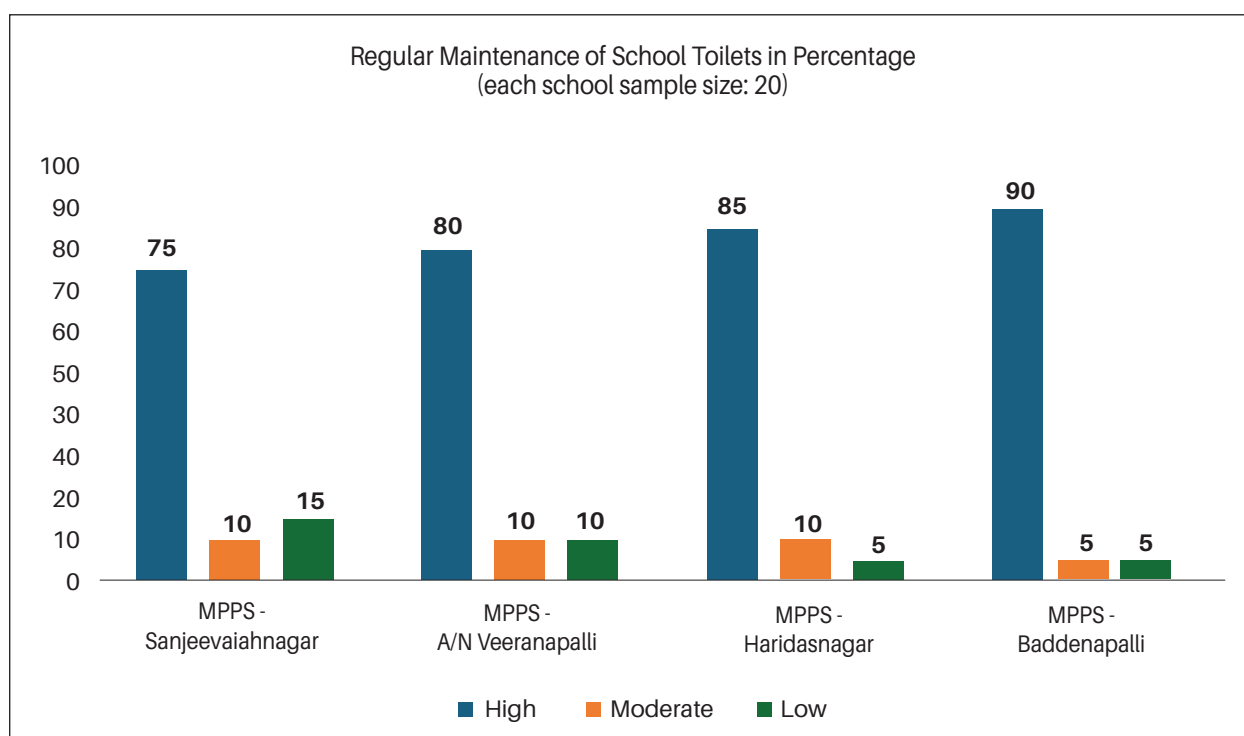
1) सरकारी स्कूलों में शौचालयों की उपलब्धता में सुधार



- एमपीपीएस-बडेनापल्ली के सभी छात्रों ने बीडीएल परियोजना के माध्यम से बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए पृथक शौचालयों की बेहतर उपलब्धता पर संतोष व्यक्त किया है।
- शेष 3 स्कूलों के छात्रों का संतुष्टि स्तर 85% से 95% के बीच था, जो स्कूल शौचालयों की बेहतर उपलब्धता के प्रति समग्र सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
- सर्वेक्षण किए गए सभी चार स्कूलों के छात्रों ने बताया कि पहले, उन्हें अपर्याप्त सरकारी शौचालयों और बेकार मौजूदा शौचालयों के कारण स्कूल परिसर के बाहर शौच का सहारा लेना पड़ता था। हालांकि, इस परियोजना ने स्कूल शौचालयों के निर्माण का नेतृत्व किया है, जिससे शौचालय सुविधाओं में सुधार हुआ है और सरकारी स्कूलों में खुले में शौच को कम किया गया है।

2) स्कूल के शौचालयों का नियमित रखरखाव

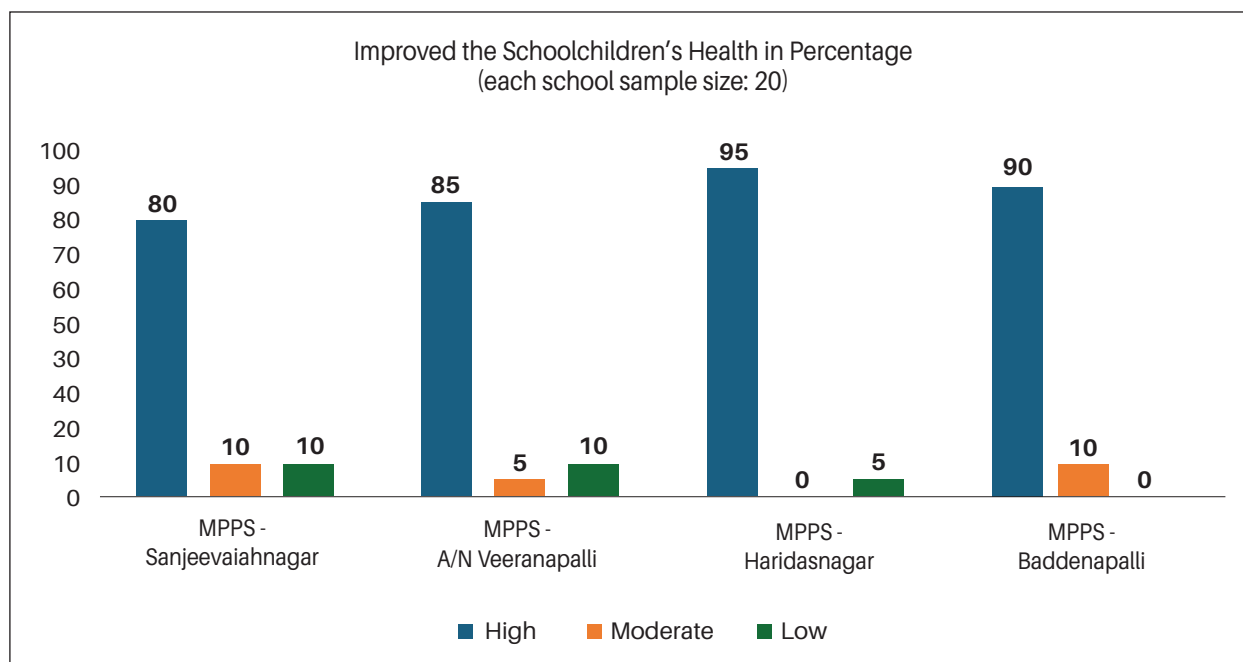
- एमपीपीएस-बडेनापल्ली के 90% छात्रों ने स्कूल के शौचालयों के नियमित रखरखाव पर संतोष व्यक्त किया, जो सभी चार स्कूलों में सबसे अधिक प्रतिशत था, अस्थायी सफाई कर्मचारियों की तैनाती और ग्राम पंचायत के समर्थन से पर्याप्त बजट आवंटन पर प्रकाश डाला।
- इसके अलावा, अन्य तीन स्कूलों के छात्रों ने 75% से 85% के बीच संतुष्टि स्तर की सूचना दी।
- इसके अलावा, एमपीपीएस-संजीवैनगर के 15% छात्रों ने स्कूल शौचालयों के नियमित रखरखाव में सुधार की आवश्यकता का संकेत दिया, हर दो दिन में एक बार के बजाय दैनिक सफाई की आवश्यकता पर बल दिया।



3) स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार

- एमपीपीएस-हरिदासनगर में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 95% छात्रों ने बीडीएल द्वारा स्कूल शौचालयों की स्थापना के बाद स्कूली बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

- शेष तीन स्कूलों के स्कूली बच्चों ने 80% से 90% के बीच अपने उच्च संतुष्टि स्तर का खुलासा किया।
- सर्वेक्षण किए गए सभी चार स्कूलों के अधिकांश छात्रों ने बताया कि परियोजना द्वारा प्रदान किए गए शौचालयों की स्वच्छता के कारण जलजनित रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, छात्रों ने उल्लेख किया कि वे अब उचित शौचालय उपयोग, हाथ धोने की प्रथाओं और शौचालयों की अच्छी स्थिति में बनाए रखने के बारे में अधिक जागरूक थे। इन कारकों ने स्वास्थ्य समस्याओं में उल्लेखनीय कमी में योगदान दिया, अंततः स्कूली बच्चों के बीच स्वास्थ्य में वृद्धि हुई।



शिक्षक संतुष्टि स्तर: आईपीई टीम ने चार प्राथमिक विद्यालयों के आठ शिक्षकों के साथ काम किया, जिनमें से सभी ने बीडीएल की परियोजना के साथ अपनी अत्यधिक संतुष्टि व्यक्त की। शिक्षकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीडीएल ने न केवल लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और मूत्रालय की पेशकश की, बल्कि उचित हाथ धोने की सुविधा, बहते पानी और एक ओवरहेड पानी की टंकी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की। इन सुविधाओं ने छात्रों की भलाई में काफी सुधार किया।

अभिभावकों की संतुष्टि का स्तर: आईपीई टीम ने चार प्राथमिक विद्यालयों के सोलह माता-पिता के साथ बातचीत की, प्रत्येक माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए अलग शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में उच्च स्तर की संतुष्टि व्यक्त की। बीडीएल द्वारा उचित बहते पानी, हाथ धोने की सुविधाओं और साइनेज के साथ शौचालय और मूत्रालय की पेशकश करने में किए गए प्रयासों की सभी ने बहुत सराहना की।

समग्र अवलोकन

- राजन्ना सिरसिला जिले के चयनित सरकारी स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्यकारी अभियंता, तेलंगाना राज्य शैक्षिक कल्याण अवसंरचना विकास निगम (ईई-टीएसईडब्ल्यूआईडीसी) द्वारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दो चरणों में किया गया था। परियोजना की कुल लागत 200 लाख रुपये थी।

- आईपीई टीम ने निर्धारित किया कि सिरसिला जिले के चार स्कूलों में बीडीएल द्वारा निर्मित स्कूल शौचालयों में उनकी यात्रा के दौरान बहते पानी का संतोषजनक स्तर था।
- आईपीई टीम ने पाया कि अधिकांश स्कूल उचित स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य प्रथाओं के साथ-साथ स्कूल टॉयलेट के उपयोग पर नियमित रूप से जागरूकता सत्र आयोजित करते हैं। इन सकारात्मक आदतों को छात्रों में डाला जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने घरों में उनका अभ्यास करते रहें।
- यह परियोजना मूल रूप से लड़कियों के लिए शौचालय ब्लॉक के निर्माण के लिए थी, लेकिन बाद में इसे लड़कों के लिए शौचालय ब्लॉक के निर्माण को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था।
- समझौता ज्ञापन के तहत, कार्यान्वयन एजेंसी ने राजन्ना-सिरसिला जिले में 64 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण पूरा किया। ये शौचालय ब्लॉक रणनीतिक रूप से छह मंडलों के भीतर 22 प्राथमिक विद्यालयों, 03 मध्य विद्यालयों और 14 जेडपीएचएस उच्च विद्यालयों में बनाए गए थे। प्रति शौचालय ब्लॉक की लागत 3.1 लाख रुपये थी।
- इस पहल ने परियोजना के हिस्से के रूप में उचित शौचालय उपयोग, अच्छी स्वच्छता प्रथाओं और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में राजन्ना-सिरसिला जिले के 39 सरकारी स्कूलों में 3000 छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाई।
- आईपीई टीम ने निरीक्षण किए गए चार स्कूलों में बीडीएल द्वारा निर्मित स्कूल शौचालय ब्लॉकों की उच्च उपयोग दर को नोट किया।

भौतिक अवलोकन

मापदण्ड का नाम	अन्वेषक अवलोकन
शौचालय की सफाई	दैनिक
शौचालय के सफाई कर्मों	स्कूलों ने शौचालय स्थानों पर सफाई कर्मियों को तैनात किया
हाथ धोने की आदतें	स्कूली बच्चे हाथ धोने की आदतों का पालन करते हैं
स्कूलों को खुले में शौच मुक्त स्थान घोषित किया गया।	हाँ
अलग मूत्रालय और शौचालय	हाँ
आसान पहुँच	हाँ
पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन	हाँ
पानी की उपलब्धता	हाँ
बहते पानी का प्रावधान	सभी स्कूलों में उपलब्ध
साबुन, स्वच्छता सामग्री और झाड़ू	सुलभ
संकेत	सुलभ

केस स्टडीज

केस स्टडी 1

“हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा की अनुपस्थिति के कारण स्कूली बच्चे स्कूल के आसपास खुले स्थानों में शौच करते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र गंदे और अस्वच्छ हो जाते हैं, जिससे छात्रों में विभिन्न स्वास्थ्य रोग फैल जाते हैं। यह स्थिति 2021-22 तक बनी रही जब बीडीएल ने स्कूल शौचालय प्रदान किए। अब, सभी छात्रों के पास पर्याप्त पानी की आपूर्ति के साथ शौचालय की सुविधा है। शिक्षक छात्रों को उचित शौचालय के उपयोग, अच्छी स्वच्छता प्रथाओं और हाथ धोने के बारे में शिक्षित करते हैं, जिससे स्कूल में शैक्षणिक और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है”।

चौधरी तिरुपति

हेडमास्टर, एमपीपीएस-बडुनापल्ली, तांगलापल्ली मंडल


केस स्टडी 2

“बीडीएल द्वारा स्थापित शौचालय अच्छी तरह से रखे गए हैं, जिनमें बहता पानी और स्वच्छता है। इसके अलावा, शिक्षक हमें उचित शौचालय उपयोग, हाथ धोने और स्वच्छता प्रथाओं पर शिक्षित करते हैं, जिससे हमारे समुदाय के भीतर स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि हुई है। हम इन आवश्यक शौचालय सुविधाओं के साथ हमें प्रदान करने के लिए बीडीएल के दिल से आभारी हैं”।

पांचवी कक्षा के छात्र

एमपीपीएस -हरिदासनगर, येल्लारेड्डीपेट मंडल, सिरसिला जिला

परियोजना 3: नौसेना अस्पताल, दिल्ली में कोविड से संबंधित उपकरणों की खरीद

परियोजना का नाम	नौसेना अस्पताल, दिल्ली में कोविड से संबंधित उपकरणों की खरीद (परियोजना निष्पादन: भारतीय नौसेना हितकारी अस्पताल)
परियोजना लागत	300 लाख
निष्पादन अवधि	2021-22
सीएसआर विषयगत क्षेत्र	आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं। (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर xii) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। (अनुसूची VII, धारा 135, मद सं. (i))
एसडीजी लक्ष्य	



परियोजना का उद्देश्य	भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके आश्रितों को लाभान्वित करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन उपचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए देश भर में भारतीय नौसेना के अस्पतालों में कोविड से संबंधित उपकरणों की खरीद करना।
कुल लाभार्थी	भारतीय नौसेना कर्मी और उनके आश्रित

परियोजना की पृष्ठभूमि

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की ऊंचाई के दौरान अप्रैल और जुलाई 2021 में भारत को प्रभावित करने वाले ऑक्सीजन आपूर्ति संकट के गहरे परिणाम हुए। देश भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कोविड -19 से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। संक्रमित व्यक्तियों की भारी मात्रा ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर महत्वपूर्ण दबाव डाला, जिससे बेड, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी हो गई। भारत को इस दूसरी लहर के दौरान एक विकट बाधा का सामना करना पड़ा, जो चिकित्सा उपकरणों और आपातकालीन देखभाल सुविधाओं में कर्मियों से उपजी संक्रमण और मृत्यु दर की उच्च दर से चिह्नित है। देश भर में स्थित भारतीय नौसेना के अस्पतालों ने भी नौसेना कर्मियों और उनके आश्रितों की देखभाल के लिए आवश्यक आपातकालीन उपचार संसाधनों और चिकित्सा आपूर्ति की कमी का अनुभव किया। इस तत्काल आवश्यकता के जवाब में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल), एक जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में, कोविड-19 और अन्य चिकित्सा आपात स्थितियों को संबोधित करने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न भारतीय नौसेना अस्पतालों को 300 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की, जैसा कि चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना द्वारा अनुरोध किया गया था। भारत सरकार। बीडीएल को इन नौसेना अस्पतालों से विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और अन्य के लिए एचक्यूडब्ल्यूएनसी और एचक्यूएसएनसी से अनुरोध प्राप्त हुए।

परियोजना की पहल

बीडीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूरे देश में कई भारतीय नौसेना अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच आपातकालीन चिकित्सा उपचार की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करना है। बीडीएल के सीएसआर फंडिंग के माध्यम से प्रत्येक नौसेना अस्पताल के लिए खरीदे गए चिकित्सा उपकरणों की बारीकियां रु. 300 लाख नीचे दी गई हैं। भारतीय नौसेना के परोपकारी ने विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की खरीद की।

अस्पताल का नाम	सामान	कुल लागत
डाइविंग स्कूल, कोच्चि	एकाधिक पैरामीटर (02 इकाइयां), आईआर थर्मामीटर (2 इकाइयां)	164800.00
आईएनएचएस, कस्तूरी	सेमीऑटोमेटेड जमावट विश्लेषक (1 इकाई), ओटी टेबल (1 इकाई), छत ओटी प्रकाश (1 इकाई), सक्शन उपकरण (1 इकाई), स्वचालित इलेक्ट्रिक डिफाइब्रिलेटर (2 इकाइयां), पूरी तरह से / स्वचालित इलेक्ट्रिक अस्पताल बिस्तर (10 इकाइयां), क्रैश कार्ट ट्रॉली (03 इकाइयां), डिजिटल बीपी उपकरण (01 इकाई)	1769002.00

अस्पताल का नाम	सामान	कुल लागत
आईएनएस, मोंडोवी	ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर (1 इकाई), ऑटोमैटिक सीपीआर डिवाइस (1 इकाई), मल्टी पैरामीटर मॉनिटर (1 इकाई)	1336194.00
आईएनएचएस, निवारिणी	ट्राइएज मीटर प्रो सिस्टम (1 इकाई), पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन (1 इकाई), एम्बुलेटरी बीपी मशीन (1 इकाई), फ्यूमिगेशन मशीन (2 इकाई), स्लिम एलईडी एक्स-रे व्यू बॉक्स सेंसर के साथ 25 मिमी (1 इकाई), एंटी-डिकुबिटस एयर बबल गद्दे (बेड सोर क्योर सिस्टम) - (4 इकाई)	1299997.00
आईएनएचएस, संजीवनी	ईसीजी मशीन (2 इकाई), इन्फ्यूजन पंप (7 इकाई), प्रेशर मॉनिटर (3 इकाई), एम्प्यूल कटर (2 इकाई), ह्यूमिडिफायर और ब्लेंडर के साथ बाल चिकित्सा वेंटिलेशन में सक्षम मैकेनिकल वेंटिलेटर (1 इकाई), मुट्टीपारा मॉनिटर (3 इकाई), कार्डिएक डिफाइब्रिलेटर (1 इकाई), पोर्टेबल एईडी (2 इकाई)	2958679.00
आईएनएचएस, नवजीवनी	नीरव सक्शन उपकरण (1 इकाई), इन्फ्यूजन पंप (4 इकाइयां)	510000.00
आईएनएचएस, अश्विनी	O2 मैन डिस्प्ले स्टेशन के साथ केंद्रीय निगरानी स्टेशन 24 मॉनिटर, रोगी वार्मर सिस्टम (2 इकाइयां), आंतरायिक वायवीय संपीड़न उपकरण (5 इकाइयां), होल्टर मॉनिटर (4 इकाइयां), नीरव सक्शन मशीन (5 इकाइयां), सिरिज जलसेक पंप (20 इकाइयां), इको प्रोबल (ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी के लिए (1 इकाई), एईडी के साथ डिफिब्रिलेटर (4 इकाइयां), एईडी (2 इकाइयां), ऊतक मोर्सेलेशन सिस्टम किट (1 इकाई), ड्रिल और देखा प्रणाली (1 इकाई), हार्मोनिक स्केलपेल (1 इकाई), 12 चैनल ईसीजी मशीन (2 इकाइयां), हम्बी चाकू (1 इकाई), 5 मिमी 30 डिग्री दूरबीन (1 इकाई), वायवीय स्लाइडिंग दरवाजा के साथ क्षैतिज आटोक्लेव (1 इकाई), गोली प्रदर्शन के साथ पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड (2 इकाइयां)	16655957.00
आईएनएचएस पतंजलि	एथिलीन ऑक्साइड स्टेरलाइजर (1 इकाई), ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर (1 इकाई), पोर्टेबल ओटी लाइट (2 इकाई), डिजिटल थर्मामीटर (2 इकाई)	725500.00
आईएनएचएस, जीवन्ती	फेको इमल्सीफिकेशन (1 इकाई), फीटल मॉनिटर (1 इकाई), ट्रांसपोर्ट इनक्यूबेटर (1 इकाई), दूरबीन माइक्रोस्कोप विथ यूएसबी कैमरा अटैचमेंट (1 इकाई), बुल नोज फिटिंग विथ कम्प्लीट सेट (2 इकाई)	4486291.00
	कुल योग	29906420.00



कोविड-19 महामारी के दौरान आईएनएचएस-अधिनी, कोलाबा, मुंबई, महाराष्ट्र (कमांड अस्पताल) के लिए खरीदे गए कोविड-19 चिकित्सा उपकरण



The IPE team member interacted with officials of Indian Naval Hospital Ship (INHS) Asvini, Colaba, Mumbai, Maharashtra (Command Hospital)

प्रभाव विश्लेषण ढांचा: आईपीई टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं।

प्रासंगिकता: इस परियोजना का बहुत महत्व है क्योंकि यह पुणे, चिल्का-ओडिशा, कोच्चि, आईएनए एझिमाला-केरल, कोलाबा-मुंबई, उत्तरी गोवा में आईएनएस अस्पताल और कोच्चि में डाइविंग स्कूल अस्पताल में स्थित कई आईएनएस अस्पतालों में कोविड-19 उपचार क्षमताओं को बढ़ाती है। महामारी के दौरान, इन अस्पतालों को मल्टीपैरा मॉनिटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, अर्ध-स्वचालित जमावट विश्लेषक, सक्शन डिवाइस, डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर, परिवहन वेंटिलेटर, फेकमूल्सीफिकेशन मशीन और कई अन्य सहित चिकित्सा उपकरणों की एक विविध सरणी की आपूर्ति की गई थी, जो हमारे सम्मानित भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों के जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा, ये नौसेना अस्पताल कोविड-19 के बाद उनके लिए उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करके असाधारण उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दक्षता: बीडीएल ने पूरे देश में पांच आईएनएस अस्पतालों, एक डाइविंग स्कूल अस्पताल और एक आईएनएस अस्पताल को चिकित्सा उपकरण, उपकरण और सुविधाएं प्रदान कीं। यह परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय नौसेना हितकारी के माध्यम से, निर्धारित समय सीमा के भीतर और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 300 लाख के बजट आवंटन के साथ पूरा किया गया था। आपूर्ति किए गए चिकित्सा उपकरण, उपकरण और सुविधाएं कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके आश्रितों के इलाज में सहायक रही हैं और इन अस्पतालों में भर्ती लोगों के लिए आपातकालीन, सर्जिकल, बाल चिकित्सा और इनपेशेंट उपचार सेवाओं का समर्थन करना जारी रखती हैं।

प्रभावशीलता: बीडीएल ने पांच आईएनएस अस्पतालों, एक आईएनएस अस्पताल और एक डाइविंग स्कूल अस्पताल के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरणों, उपकरणों और सुविधाओं की एक श्रृंखला प्रदान करके इस परियोजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नतीजतन, इस पहल ने

कोविड-19 के उपचार प्रोटोकॉल में काफी सुधार किया है, अंततः भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके आश्रितों के जीवन को बचाया है जो संक्रमित थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना ने इन अस्पतालों में उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के माध्यम से आउट पेशेंट, इनपेशेंट, आपातकालीन और सर्जिकल उपचार की क्षमता को बढ़ाया है।

प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने भारतीय नौसेना के अस्पतालों में उपचार सुविधाओं के विकास में तेजी लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर दिया है। इस परियोजना ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये अस्पताल भविष्य में होने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति का समाधान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों, उन्नत उपकरणों और बढ़ी हुई सुविधाओं की बढ़ती उपलब्धता के परिणामस्वरूप आपातकालीन उपचार के लिए आवश्यक समय में उल्लेखनीय कमी आई है। नतीजतन, उन्नत सुविधाओं ने न केवल अस्पताल सेवाओं की समग्र प्रभावशीलता में सुधार किया है, बल्कि भारतीय सेना से जुड़े कई व्यक्तियों और उनके आश्रितों के जीवन की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान की गई प्रगति ने सैन्य ढांचे के भीतर स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए एक नया मानक स्थापित किया है, जिससे भविष्य के किसी भी स्वास्थ्य संकट के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित हो गई है।

सम्बद्धता: बीडीएल ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली तत्काल उपचार आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए भारतीय नौसेना अस्पतालों के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया है। यह प्रयास भारतीय नौसेना के अस्पतालों की क्षमताओं को उन्नत करके भारत सरकार की कोविड-19 राहत रणनीतियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था।

परिणाम

- देश भर में स्थित भारतीय नौसेना अस्पतालों में चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना।
- इस परियोजना ने भारतीय नौसेना और उनके आश्रितों के कई जीवन बचाए।

स्थिरता: चिकित्सा उपकरणों, उपकरणों और विभिन्न सुविधाओं के लगातार रखरखाव और कामकाज के कारण परियोजना के परिणामों का निरंतर प्रभाव पड़ता है। नियमित रखरखाव के कारण, इन चिकित्सा संसाधनों का उपयोग अब नौसेना और उनके आश्रितों के भीतर सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए नियमित और आपातकालीन उपचार दोनों में ठीक से किया जाता है।

परियोजना का प्रदर्शन

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर
प्रासंगिकता	अति उत्कृष्ट	19
दक्षता	अति उत्कृष्ट	17
प्रभावशीलता	अति उत्कृष्ट	17
प्रभाव	अति उत्कृष्ट	18
स्थिरता	अति उत्कृष्ट	17
कुल स्कोर	अति उत्कृष्ट	88


व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत खराब: 1 to 4

कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत खराब (1 to 20)

समग्र अवलोकन

- सभी अस्पतालों में विभिन्न विभागों में यह उपकरण पूर्ण उपयोगिता में है।
- परियोजना ने देश भर में भारतीय नौसेना अस्पतालों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के मूल्य को बढ़ाने के लिए समर्थन बढ़ाया है।
- परियोजना का प्रभाव बहुत अधिक है।

परियोजना 4: भानूर गांव में जिला परिषद हाई स्कूल का निर्माण

परियोजना का नाम	भानूर गाँव में जिला परिषद हाई स्कूल का निर्माण
परियोजना लागत	324 लाख
निष्पादन अवधि	20.02.2020 और 17.03.2022
सीएसआर विषयगत क्षेत्र	शिक्षा को बढ़ावा देना (अनुसूची VII, धारा 135, मद सं. 2)
एसडीजी लक्ष्य	
परियोजना का उद्देश्य	ग्राम भानूर में जिला परिषद हाई स्कूल में विशाल विद्यालय भवन का निर्माण कर कक्षा शिक्षण और अधिगम सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
कुल लाभार्थी	145 स्कूली बच्चे (75 लड़के + 70 लड़कियां) - छठी से दसवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं

परियोजना की पृष्ठभूमि

जिला परिषद हाई स्कूल (जेडपीएचएस), भानूर, 1989 में सह-शिक्षा विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। इस शैक्षणिक संस्थान ने तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले में स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र भानूर गांव में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में, स्कूल में कुल 145 छात्रों का नामांकन है, जिसमें 75 लड़के और 70 लड़कियां शामिल हैं। शिक्षण स्टाफ में 9 सदस्य होते हैं, जबकि 3 गैर-शिक्षण स्टाफ सदस्य होते हैं। इन वर्षों में, स्कूल ने उल्लेखनीय शैक्षणिक सफलता हासिल की है। हालांकि, इसे कक्षा के बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कक्षाओं की सीमित संख्या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी, जिसमें रिसाव, दीमक से क्षति और दिखाई देने वाली दरारें जैसी समस्याएं थीं। इसके अतिरिक्त, स्कूल में उचित शौचालय सुविधाओं,



पेयजल, खेल सुविधाओं और अन्य आवश्यकताओं का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप छात्र नामांकन में गिरावट आई थी। हर साल, स्कूल मरम्मत, रखरखाव और आवश्यक सेवाओं के लिए सरकार से धन सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करता था। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, स्कूल ने बीडीएल के सीएसआर फंड से समर्थन सुरक्षित करने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों और प्रभावशाली व्यक्तियों को सक्रिय रूप से शामिल किया। बीडीएल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूल के अट्रट समर्पण से बहुत प्रभावित हुआ, जिससे स्कूल भवन के निर्माण और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना का समर्थन हुआ। स्कूल भवन का निर्माण 20 फरवरी, 2020 को शुरू हुआ और 17 मार्च, 2022 तक पूरा हो गया। इस परियोजना पर कुल 324 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

परियोजना की पहल

परियोजना शुरू की गई: 10 दिसंबर 2019

काम शुरू होने की तारीख: 20 फरवरी 2020

काम पूरा होने की तिथि: 17.03.2022

कार्य ऑर्डर मूल्य: Rs. 27819290.01; वास्तविक कार्य निष्पादन मूल्य: रु. 32379177.97 (लगभग 324 लाख)

Construction details of School Building

कुल प्लॉट क्षेत्र	1 एकड़
भूतल, पहली मंजिल और मुमटी सहित कुल निर्मित क्षेत्र	1680 वर्गमीटर
कारपेट एरिया	1092.00 वर्गमीटर
भूतल और पहली मंजिल पर कक्षाओं की संख्या	22
कक्षा सुविधाएं	प्रत्येक कक्षा में डाई, ब्लैकबोर्ड और बैठने की व्यवस्था की गई थी
प्रत्येक कक्षा में विद्युत जुड़नार	कमरे के आकार के अनुसार प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त पंखे, ट्यूब लाइट और बिजली की सुविधा उपलब्ध थी।
शौचालय	लड़कों, लड़कियों और शिक्षकों के लिए अलग टॉयलेट ब्लॉक
पीने का पानी और खेल सुविधाएं	सुलभ

प्रभाव विश्लेषण ढांचा: आईपीई टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं।

प्रासंगिकता: यह परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आरटीई अधिनियम 2009 के साथ संरेखित है, दोनों ही एक आदर्श सीखने के माहौल बनाने के महत्व को उजागर करते हैं, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, प्रौद्योगिकी, खेल / मनोरंजन क्षेत्र, छात्र चर्चा स्थान और सरकारी स्कूलों में भोजन क्षेत्र शामिल हैं। इन नीतियों के अनुसार, इस परियोजना ने पर्याप्त कक्षाओं, एक किचन हॉल, एक पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, स्टाफ रूम, शौचालय, भंडारण कक्ष, एक चारदीवारी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ एक खेल का मैदान विकसित करके भानूर गांव में जिला परिषद हाई स्कूल की जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

दक्षता: नियत समय सीमा और बजट के भीतर, परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की गई। इससे विशाल कक्षाओं, प्रयोगशाला सुविधाओं, एक पुस्तकालय, सेमिनार हॉल, रसोई और भोजन क्षेत्र, स्टाफ रूम, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए स्थान, खेल क्षेत्र, एक स्कूल की चारदीवारी के साथ-साथ शौचालय और पीने के पानी की सुविधाओं सहित कई सुविधाओं की स्थापना हुई। स्कूल प्रबंधन अनुकूल सीखने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर रहा है, जिससे छात्रों की शैक्षणिक उन्नति और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

प्रभावशीलता: परियोजना ने कक्षा VI से X में 145 छात्रों के लिए सीखने को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाकर अपने उद्देश्य को बड़ी प्रभावशीलता के साथ पूरा किया है। स्कूल भवन के निर्माण के बाद, कक्षा निर्देश, पाठ्येतर गतिविधियों, खेल प्रावधानों, दोपहर के भोजन के दौरान छात्र सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच और टॉयलेट सुविधाओं में सुधार देखा गया। इन प्रावधानों से शैक्षिक मानकों की गुणवत्ता में काफी वृद्धि हुई है।

प्रभाव: इस परियोजना से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसे कि स्कूल नामांकन में वृद्धि, छात्रों की अनुपस्थिति में कमी और छात्रों के बीच शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि। इसके अतिरिक्त, इस प्रयास ने स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, पौष्टिक मध्याह्न भोजन और खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करके बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके अलावा, भानूर गांव में निष्पादित परियोजना ने न केवल शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन लाए हैं, बल्कि निवासियों के बीच भविष्य के लिए आशा और सकारात्मक सोच की भावना भी पैदा की है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे शिक्षा और समुदाय संचालित पहल हाशिए के समुदायों का विकास और सशक्तिकरण कर सकती हैं।

सम्बद्धता: यह परियोजना तेलंगाना सरकार और भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कूली शिक्षा पर विभिन्न नीतियों के अनुसार है।

परिणाम

- कक्षा शिक्षण और अधिगम वातावरण में संवर्द्धन किए गए हैं।
- पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार।
- खेल सुविधाओं में वृद्धि।
- स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार।

स्थिरता: परियोजना की उपलब्धियों का स्थायी प्रभाव भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा स्कूल भवन के उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके अलावा, परियोजना ने कक्षा सुविधाओं की पेशकश के अलावा, पेयजल, स्वच्छता, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए स्थायी प्रावधान भी स्थापित किए। इन स्थायी परियोजना परिणामों को बनाए रखने की स्कूल की क्षमता सरकारी स्कूल निधियों से निरंतर वित्तीय सहायता और ग्राम पंचायत से सहायता के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।





बीडीएल परियोजना से पहले: गांव भानूर के जिला परिषद उच्च विद्यालय में जर्जर स्कूल भवन की स्थिति



बीडीएल परियोजना के बाद: भानूर गांव के जिला परिषद हाई स्कूल में सभी सुविधाओं के साथ विशाल कक्षाएं

परियोजना का प्रदर्शन

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

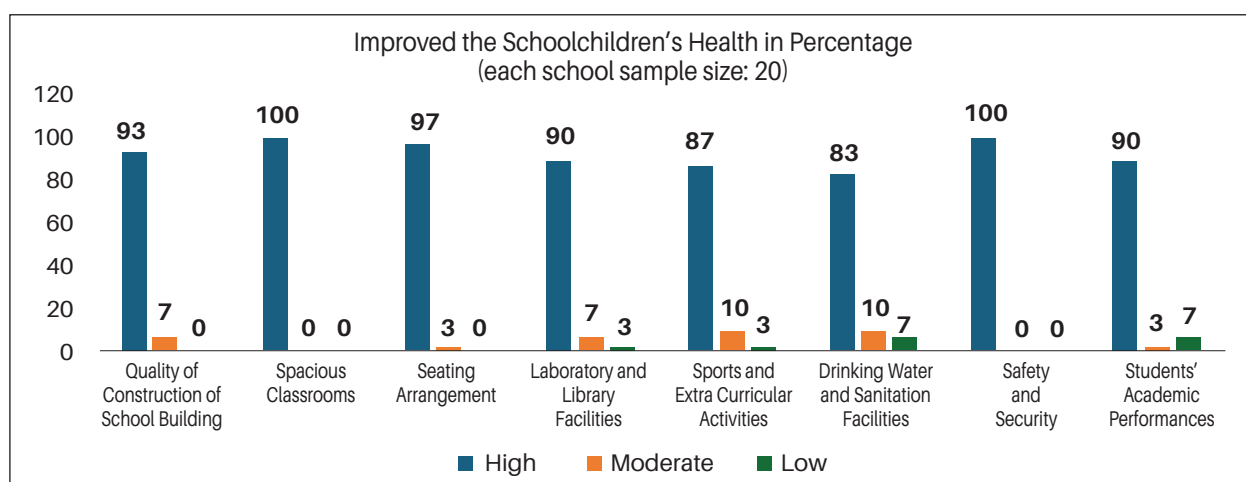
डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर
प्रासंगिकता	औसत से ऊपर	16
दक्षता	औसत से ऊपर	15
प्रभावशीलता	औसत से ऊपर	15
प्रभाव	औसत से ऊपर	15
स्थिरता	औसत से ऊपर	15
कुल स्कोर	औसत से ऊपर	76

व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत खराब: 1 to 4

कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत खराब (1 to 20)

संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

अ) छात्र: आईपीई टीम ने नौवीं और दसवीं कक्षा के पिछड़े 30 छात्रों को एक सर्वेक्षण प्रश्नावली वितरित की, जिसमें 15 पुरुष और 15 महिला छात्रों के बराबर विभाजन था। बीडीएल परियोजना के लिए भवन के निर्माण की गुणवत्ता के बारे में छात्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक रही है। अधिकांश छात्रों ने विशाल कक्षाओं और बैठने की व्यवस्था के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त की, जो एक अनुकूल सीखने के माहौल में योगदान करते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नया स्कूल भवन न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि अकादमिक फोकस को भी बढ़ावा देता है।



स्कूल का वातावरण छात्रों को उनके शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नतीजतन, छात्र उत्सुकता से स्कूल जाने और इन सुविधाओं से लाभान्वित होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छात्र बीडीएल द्वारा प्रदान किए गए अच्छी तरह से बनाए गए टॉयलेट और वाशिंग क्षेत्रों को महत्व देते हैं, जो स्कूल

के घंटों के दौरान स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में मदद करते हैं। सामान्य तौर पर, छात्र इस पहल के माध्यम से पेश किए गए विशेष खेल क्षेत्र, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय सुविधाओं और भंडारण कक्षों के साथ अत्यधिक संतुष्ट हैं।

ब) शिक्षक: आईपीई टीम ने जिला परिषद हाई स्कूल - भानूर के दस शिक्षकों के साथ उपयोगी बातचीत की, जिनमें से सभी ने कक्षा शिक्षण, सीखने के माहौल, पुस्तकालय सुविधाओं, प्रयोगशाला संसाधनों, पाठ्येतर गतिविधियों, और छात्र सुविधाओं जैसे पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा और सुरक्षा में हुई प्रगति के साथ अपनी उच्च स्तर की संतुष्टि व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन संवर्द्धन ने शिक्षा और छात्र सुविधाओं की गुणवत्ता में काफी वृद्धि की है, जैसा कि इस पहल के सफल समापन के बाद दसवीं कक्षा की परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन से पता चलता है।

स) अभिभावक: उनकी बातचीत के दौरान, आईपीई टीम को दस माता-पिता से अनुकूल प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें से सभी ने विशाल कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशाला के साथ अपनी उच्च संतुष्टि व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों और छात्र सुविधाओं जैसे पेयजल, टॉयलेट सुविधाओं, पाठ्येतर गतिविधियों और खेल की पहुंच के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की, जो इस परियोजना द्वारा संभव हुए हैं।

समग्र अवलोकन

- बीडीएल ने भूतल और प्रथम तल दोनों पर 11 कक्षाओं का निर्माण किया है, जिसमें कुल 22 कमरे हैं। इनमें से, 10 कक्षाएं शिक्षण के लिए समर्पित हैं, दो कमरे प्रयोगशालाओं के रूप में नामित हैं, तीन कमरे पुस्तकालय और छात्रों की पाठ्येतर गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए हैं, दो कमरे प्रधानाध्यापिका और कर्मचारियों के लिए सौंपे गए हैं, दो कमरे भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं, और तीन कमरे विभिन्न कक्षाओं में अतिरिक्त वर्गों के भविष्य के विस्तार के लिए आरक्षित हैं।
- बीडीएल ने छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण किया है। लड़कों के टॉयलेट में 4 मूत्रालय और 5 IWC शौचालय हैं, जबकि लड़कियों के टॉयलेट में 4 IWC शौचालय हैं। इसके अतिरिक्त, बीडीएल ने पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए अलग-अलग टॉयलेट ब्लॉक भी बनाए हैं, साथ ही हेडमिस्ट्रेस के लिए टॉयलेट-कम-बाथरूम भी बनाया है। पुरुष टॉयलेट में दो मूत्रालय और एक डब्ल्यूसी शौचालय है, जबकि महिला टॉयलेट में डब्ल्यूसी शौचालय और हाथ धोने के स्टेशन हैं।
- इस परियोजना ने एक उपयुक्त कक्षा सेटिंग के निर्माण, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान, मध्याह्न भोजन के लिए सुविधाओं में वृद्धि, और खेल और पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के माध्यम से शैक्षिक अनुभव में समग्र रूप से सुधार किया है। इन प्रयासों ने समग्र रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को काफी मजबूत किया है।

केस स्टडीज

केस स्टडी 1

“बीडीएल द्वारा भानूर में जिला परिषद हाई स्कूल में स्कूल भवन का निर्माण एक प्रभावशाली वास्तुशिल्प उपलब्धि को दर्शाता है। यह कक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, प्रत्येक को एक आदर्श सीखने के माहौल बनाने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। ये कक्षाएं अच्छी तरह हवादार हैं, बैठने की उपयुक्त व्यवस्था, पॉडियम और ब्लैकबोर्ड से सुसज्जित हैं। इसके अलावा, परियोजना में एक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सुविधाओं और विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों के लिए समर्पित स्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए अलग-

अलग शौचालय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस व्यापक दृष्टिकोण ने कक्षा शिक्षण और सीखने के तरीकों को काफी बढ़ाया है, छात्रों की शैक्षणिक यात्रा और समग्र विकास को बढ़ावा दिया है, जिसमें उनकी शैक्षिक प्रगति और कल्याण पर एक मजबूत ध्यान दिया गया है।


श्रीमती दक्षायिनी,
प्रधानाध्यापिका, जिला परिषद हाई स्कूल, भानूर

केस स्टडी 2

“बीडीएल की परियोजना के कार्यान्वयन से पहले, जब मैं छठी कक्षा में था, मेरी कक्षाएं असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण कक्षाओं में आयोजित की जाती थीं, जिससे हमारे सीखने के अनुभव में बाधा उत्पन्न होती थी। हालांकि, सामाजिक रूप से जागरूक संगठन बीडीएल ने भानूर में जिला परिषद हाई स्कूल के लिए एक नई, विशाल इमारत का निर्माण करके इस समस्या को दूर किया। इस पहल ने सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ एक अनुकूल सीखने का माहौल बनाया है, जिससे छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और समग्र विकास में सुधार हुआ है”।

साई कार्तिक,
IX कक्षा, जिला परिषद हाई स्कूल, भानूर

परियोजना 5: लखनऊ में कोविड अस्पताल के निर्माण में योगदान (2021-22)

परियोजना का नाम	लखनऊ में कोविड अस्पताल के निर्माण में योगदान (2021-22)
परियोजना लागत	200 लाख
निष्पादन अवधि	2021-22
सीएसआर विषयगत क्षेत्र	आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं। (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर xii) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर (i))
एसडीजी लक्ष्य	
परियोजना का उद्देश्य	लखनऊ में एक कोविड-19 अस्पताल स्थापित करने के लिए डीआरडीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
कुल लाभार्थी	कोविड-19 संक्रमित मरीज



परियोजना की पृष्ठभूमि

वर्ष 2021 में, कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बीच, भारत सरकार ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सुसज्जित अस्थायी कोविड केंद्र स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए। अटल बिहारी वाजपेयी अस्थायी कोविड केयर सेंटर नाम की यह पहल महामारी की दूसरी लहर के गंभीर प्रभाव को दूर करने की तत्काल आवश्यकता की प्रतिक्रिया थी। केंद्र के लिए साइट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में आवंटित की गई थी, और निर्माण की समग्र जिम्मेदारी डीआरडीओ ने निभायी थी, जिसमें मुख्य निर्माण अभियंता (सीसीई), उत्तर ने एक पखवाड़े के भीतर सफलतापूर्वक स्थापना को पूरा किया था। केंद्र 500 बेड, एक 40 केएलडी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन गैस आपूर्ति प्रणाली, गहन देखभाल इकाइयों, वेंटिलेटर, एक प्रयोगशाला, एक औषधालय और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित था। डीआरडीओ ने ऑपरेशन की सुविधा भी प्रदान की और केंद्र के संचालन की पूरी अवधि (5 मई, 2021 से 31 मार्च, 2022) के लिए चिकित्सा कर्मचारी प्रदान किए। इस पहल के लिए लगभग पच्चीस करोड़ रुपये की धनराशि पीएम केयर्स से 60% और सीएसआर से 40% के साथ भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद जैसे संगठनों के योगदान से जुटाई गई थी। इस महत्वाकांक्षी उद्यम ने हजारों गंभीर रूप से बीमार रोगियों को समय पर चिकित्सा देखभाल और जीवन रक्षक उपचार प्रदान किया।

परियोजना की पहल

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निर्देशों के अनुसार, डीआरडीओ के अध्यक्ष ने सीसीई से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में एक अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया। यह निर्देश अप्रैल 2021 में कोविड मामलों में वृद्धि के दौरान पीएमओ से डीआरडीओ को रिले किया गया था। पीएमओ के निर्देश के बाद डीआरडीओ ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) से वित्तीय सहायता मांगी। अपील के जवाब में, बीडीएल ने 2 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी और इसे वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान डीआरडीओ को वितरित किया।

डीआरडीओ ने योजना और वित्त पोषण पूरा करने के बाद सीसीई के समर्थन से 26 अप्रैल, 2021 को परियोजना गतिविधियों की शुरुआत की। निविदाएं जारी की गईं, जिससे कई एजेंसियां आकर्षित हुईं। सरकारी नियमों का पालन करते हुए एक सप्ताह के भीतर ठेके दिए गए। कोविड-19 सुविधा ने 05 मई, 2021 को एक अस्पताल में 500 बेड, एक अस्थायी संरचना में 200 और एक मौजूदा इमारत में 300 बेड के साथ संचालन शुरू किया। अस्पताल खुलने से पहले प्रशिक्षण और गुणवत्ता जांच की गई। इस सुविधा में सभी बिस्तरों के लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली थी। वेंटिलेटर के साथ 150 आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 350 बेड उपलब्ध थे। सेना के डॉक्टरों से मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। देश भर के चिकित्साकर्मियों ने अस्पताल का प्रबंधन किया। प्रवेश एक शहरव्यापी नियंत्रण केंद्र द्वारा समन्वित किया गया था।



डीआरडीओ ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी अस्थायी कोविड केयर सेंटर की स्थापना की

प्रभाव विश्लेषण ढांचा: आईपीई टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं।

प्रासंगिकता: उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी लगभग 240 मिलियन है। कोविड -19 से यह राज्य काफी प्रभावित हुआ है। अप्रैल 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 21,21,718 रिकवरी और 23,713 मृत्यु के साथ राज्य में 21,45,490 मामले दर्ज हुए। अकेले लखनऊ में 2,38,664 पुष्ट मामले सामने आए हैं। पर्याप्त सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा होने के बावजूद, यह विशेष रूप से महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असमर्थ रहा है। इसके जवाब में डीआरडीओ ने पीएमओ के निर्देशन में स्थानीय आबादी और आसपास के क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में एक अस्थायी कोविड केयर सेंटर की स्थापना की, जिसमें बीडीएल ने इस अस्पताल की स्थापना के लिए डीआरडीओ को अपनी सीएसआर वित्तीय सहायता प्रदान की।

दक्षता: डीआरडीओ ने सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर केंद्र को कुशलतापूर्वक स्थापित किया। तात्कालिकता के बावजूद, सीसीई ने उपकरण प्राप्त करने और आवश्यक कार्यों को पूरा करते समय सभी खरीद नियमों और विनियमों का सावधानीपूर्वक पालन किया। इन सभी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए किया गया।

प्रभावशीलता: लखनऊ में अस्थायी कोविड-19 अस्पताल की स्थापना के बाद यह उद्देश्य हासिल किया गया। गंभीर रोगियों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं और सर्वोत्तम उपलब्ध उपचार प्रदान किया गया। इस प्रयास ने पीएमओ के लिए एक चुनौती पेश की, लेकिन डीआरडीओ के प्रभावी समन्वय के साथ, कई कोविड रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया, अंततः कई लोगों की जान बच गई।

परिणाम: अस्थायी केंद्र की स्थापना के बाद, 5 मई 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान लखनऊ के इस अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार हजारों रोगियों को चिकित्सा और जीवन रक्षक उपचार प्राप्त हुआ।

प्रभाव: लखनऊ में 500 बिस्तरों वाले अटल बिहारी वाजपेयी अस्थायी कोविड केयर सेंटर के निर्माण ने 5 मई 2021 से दूसरी लहर के समापन तक कई कोविड-19 रोगियों को उपचार की पेशकश की, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम हुआ। यह केंद्र संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए तीसरी लहर की तैयारी में स्थापित किया गया था। इसके बाद, कोविड-19 के बोझ को पूरी तरह से कम करने के बाद चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं को वैकल्पिक उपचार के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियों में स्थानांतरित कर दिया गया।

सम्बद्धता: बीडीएल ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लखनऊ में 500 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड-19 अस्पताल स्थापित करने में डीआरडीओ की सहायता की। डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बीडीएल ने भारत सरकार के कोविड-19 आपदा राहत प्रयासों के अनुरूप 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का योगदान दिया।

स्थिरता: 31 मार्च, 2022 को लखनऊ में कोविड-19 हॉस्टल के बंद होने के बाद भी इस परियोजना के परिणाम स्थायी साबित हुए हैं, क्योंकि मामले घटते जा रहे हैं। इससे अस्पताल के संसाधनों और चिकित्सा उपकरणों को उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करना पड़ा। इसके बाद, उपकरण राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों को आवंटित किए गए, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में वृद्धि हुई।



परियोजना का प्रदर्शन

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर
प्रासंगिकता	अति उत्कृष्ट	19
दक्षता	अति उत्कृष्ट	18
प्रभावशीलता	अति उत्कृष्ट	18
प्रभाव	अति उत्कृष्ट	18
स्थिरता	अति उत्कृष्ट	17
कुल स्कोर	अति उत्कृष्ट	90

व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत खराब: 1 to 4

कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत खराब (1 to 20)

संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

अस्थायी सुविधा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के जवाब में स्थापित की गई थी, और एक बार स्थिति में सुधार होने के बाद, सभी उपकरण उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को आवंटित किए गए थे। मूल्यांकन के दौरान जमीन पर निरीक्षण करने के लिए बहुत कम था क्योंकि महामारी के दौरान आपातकालीन उपचार सुविधा के रूप में अपने उद्देश्य की सेवा के बाद अस्थायी केंद्र को बंद कर दिया गया था। नतीजतन, परियोजना टीम को परियोजना के दृष्टिकोण, अनुभवों और सीखे गए पाठों के साथ-साथ समुदाय पर इसकी उपयोगिता और प्रभाव पर डेटा इकट्ठा करने के लिए जनता के साथ प्रमुख मुखबिर साक्षात्कार के लिए अध्ययन के दायरे को सीमित करना पड़ा। आईपीई टीम ने जनता के 10 व्यक्तियों के साथ बातचीत की, जिनमें से सभी ने इस कोविड अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित रोगियों को दिए जाने वाले व्यापक उपचारों के साथ अपनी उच्च स्तर की संतुष्टि व्यक्त की। उनकी सकारात्मक टिप्पणियां वायरस प्रबंधन और उपचार में स्वास्थ्य पेशेवरों के समर्पण और विशेषज्ञता का द्योतक हैं।

समग्र अवलोकन

- परियोजना के कार्यान्वयन को पीएम केयर्स और सीएसआर फंड दोनों से वित्तीय सहायता मिली। सबसे अधिक फंडिंग पीएम केयर्स से आई, शेष राशि सीएसआर फंड से प्राप्त की गई। बीडीएल सहित नौ एजेंसियां सीएसआर फंड प्रदान कर रही थीं।
- कुल लगभग 25 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसमें पीएमकेयर्स का योगदान 60% और सीएसआर फंड ने शेष 40% का योगदान दिया। अप्रैल 2021 में, विभिन्न एजेंसियों से धन जुटाया गया था। डीआरडीओ को बीडीएल ने 2 करोड़ रुपये मंजूर किए और इसे डीआरडीओ को हस्तांतरित कर दिया।
- सशस्त्र बलों की एक टीम, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञताओं, नर्सों और पैरामेडिक्स के साथ डॉक्टर शामिल थे, ने इस अस्पताल का संचालन किया। अस्थायी सुविधा की स्थापना पर, गंभीर रोगियों को उचित चिकित्सा ध्यान और सर्वोत्तम संभव उपचार दिया गया।

- सीसीई और डीआरडीओ ने पीएमओ के विनिर्देशों के अनुसार एक सराहनीय पहल को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। आगे बढ़ते हुए, सरकार के पास सीसीई और डीआरडीओ द्वारा नियोजित व्यापक परियोजना कार्यान्वयन पद्धतियों के साथ-साथ उनकी उपलब्धियों का खुलासा करने का अवसर है। यह पारदर्शिता नीति निर्माताओं, निवेशकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह समझने में सक्षम करेगी कि कोविड, प्लेग, डेंगू, H5N1 और अन्य जैसी महामारी की स्थिति में समान परिणामों को कैसे पुनः उत्पन्न किया जाए।



अटल बिहारी वाजपेयी कोविड केयर अस्पताल, लखनऊ, उत्तरप्रदेश का मुख्य प्रवेश द्वार



अटल बिहारी वाजपेयी कोविड केयर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट (40 केलडी) स्थापित किया गया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश



वेंटिलेटर सुविधा के साथ आईसीयू बेड



ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ सामान्य बेड



सामान्य वार्ड के प्रवेश द्वार के अंदर




पीपीई किट में चिकित्सा और सहायक कर्मचारी



कोविड-19 मरीज परिवार के सदस्यों के रहने के लिए लगाए टेंट

परियोजना 6: सैन्य अस्पताल, सिकंदराबाद और ईएसआईसी अस्पताल, सनत नगर, हैदराबाद में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का संस्थापन

परियोजना का नाम	सैन्य अस्पताल, सिकंदराबाद और ईएसआईसी अस्पताल, सनत नगर, हैदराबाद में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का संस्थापन
परियोजना लागत	188.80 लाख
निष्पादन अवधि	जून 2021 to सितम्बर 2021
सीएसआर विषयगत क्षेत्र	आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं। (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर xii) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर (i))
एसडीजी लक्ष्य	
परियोजना का उद्देश्य	सैन्य अस्पताल, सिकंदराबाद और ईएसआईसी अस्पताल, सनत नगर, हैदराबाद में दो 960 एलपीएम ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों का निर्माण करके ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए।
कुल लाभार्थी	i) तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से सशस्त्र बलों के कर्मी और उनके परिवार ii) ईएसआईसी-बीमित व्यक्ति और उनके आश्रित

परियोजना की पृष्ठभूमि

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान अप्रैल और जुलाई 2021 में भारत को प्रभावित करने वाले ऑक्सीजन आपूर्ति संकट के गंभीर परिणाम हुए। देश भर के अस्पतालों ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, जिससे कोविड-19 से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। संक्रमित रोगियों की भारी संख्या ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप बेड, ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी हो गई। तेलंगाना राज्य को दूसरी लहर के दौरान एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसमें संक्रमण और मृत्यु दर की उच्च दर का सामना करना पड़ा। सिकंदराबाद के सैन्य अस्पताल और हैदराबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी को दूर करने के लिए, बीडीएल ने कोविड-19 उपचार के लिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 960 लीटर की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की पहल की। यह शुरुआत जून 2021 से सितंबर 2021 तक कोविड-19 की दूसरी लहर के अंत में हुई, महामारी की प्रत्याशा तीसरी लहर और अन्य स्वास्थ्य संकटों की तैयारी में है।

परियोजना की पहल

क्रम संख्या	परियोजना का स्थान	एलपीएम में ऑक्सीजन संयंत्र की क्षमता	संयंत्र की लागत	कुल अस्पताल क्षमता	प्रत्येक ऑक्सीजन प्लांट से जुड़े बेड की कुल संख्या
1	सैन्य अस्पताल, सिकंदराबाद	960	94.4 लाख	800 बिस्तर वाला	330 बिस्तर
2	ईएसआईसी अस्पताल, सनत नगर	960	94.4 लाख	490 बिस्तर वाला	200 बिस्तर



बीडीएल ने हैदराबाद के सनत नगर में ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र संस्थापित किया

ऑक्सीजन संयंत्र की तकनीकी विशेषता

संपीड़ित वायु प्रणाली से शुद्ध (नमी और तेल मुक्त) हवा, आणविक चलनी (जिओलाइट प्रकार) से भरे टावरों में से एक से गुजरती है। छलनी चुनिंदा रूप से नाइट्रोजन को अवशोषित करती है, जिससे ऑक्सीजन वांछित शुद्धता स्तर पर गुजर सकती है।

ऑक्सीजन शुद्धता: $93 \pm 3\%$; ऑक्सीजन दबाव: 4 - 5 बार ए; हवा का दबाव: 7 बार ग्राम

एयर इनलेट तापमान: 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम; परिवेश का तापमान: 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम

वायु गुणवत्ता: आईएसओ 8573 - 2010 कक्षा 1-4-1

एलपीएम	क्षमता क्यूबिकमीटर/ घंटा	समकक्ष		वायु आवश्यकताएं (कॉम्प शक्ति)			कुल मिलाकर आयाम लम्बाई X चौड़ाई X ऊंचाई (फीट) (लगभग)
		तरल ऑक्सीजन लीटर /दिन	प्रति दिन सिलेंडरों की संख्या	सीएफएम	दबाव किलोग्राम/ वर्गसेंटीमीटर में	शक्ति किलोवाट में	
960	57.6	1728	170-220	525	7	75	7 x 9 x 7

अस्पताल संक्षिप्त प्रोफाइल

सैन्य अस्पताल – सिकंदराबाद

सिकंदराबाद के केंद्र में स्थित, 490 बिस्तरों वाला अस्पताल स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के गढ़ के रूप में खड़ा है, जो

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बहादुर सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों की सेवा के लिए समर्पित है। सेवा में डूबी विरासत और दयालु देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, यह संस्थान सिर्फ एक चिकित्सा सुविधा से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है - यह हमारे राष्ट्र की सेवा करने वालों के लिए अटूट समर्थन की परंपरा का प्रतीक है। अस्पताल सशस्त्र बलों के कर्मियों की अनूठी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रत्येक दिन, औसतन 900 रोगी ओपीडी सेवाओं का उपयोग करते हैं, जबकि 250 रोगी इन-पेशेंट सेवाओं का उपयोग करते हैं।

ईएसआईसी अस्पताल प्रोफाइल

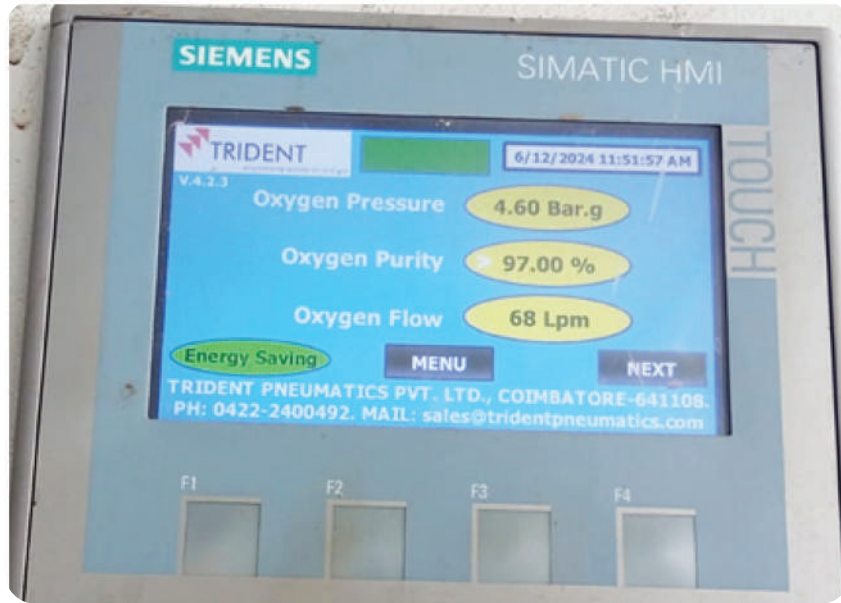
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सनत नगर, हैदराबाद एक 800 बिस्तरों वाला अस्पताल है जो तेलंगाना में ईएसआई योजना के तहत कवर किए गए 14 लाख से अधिक बीमित व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। कोविड के दौरान इस अस्पताल ने कोविड और गैर-कोविड दोनों सेवाएं प्रदान की हैं। इस अस्पताल में हर दिन 2400 से अधिक मरीजों की संख्या है। प्रत्येक दिन, अस्पताल के 90% बेड इनपेशेंट सेवाओं को प्राप्त करने वाले रोगियों द्वारा लिए जाते हैं।

प्रभाव विश्लेषण ढांचा: आईपीई टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं।

प्रासंगिकता: तेलंगाना और देश के अन्य हिस्सों में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के साथ, ऑक्सीजन की मांग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। इस गंभीर स्थिति के जवाब में, सामाजिक रूप से जागरूक संगठन बीडीएल ने प्रसिद्ध अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना शुरू करके तत्काल कार्रवाई की है। ऐसा ही एक अस्पताल सिकंदराबाद में स्थित सैन्य अस्पताल है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों की सेवा करता है। इसके अतिरिक्त, तेलंगाना राज्य में ईएसआईसी-बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाने वाला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र से लैस किया गया है। यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने इन प्रतिष्ठित अस्पतालों में 960 एलपीएम की क्षमता वाले दो ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। नतीजतन, विभिन्न उपचारों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है।

दक्षता: बीडीएल ने तेलंगाना राज्य में दो ऑक्सीजन प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं, जो आवंटित समय सीमा और बजट के भीतर परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इन संयंत्रों के लिए कुल पूंजीगत व्यय लगभग 188.80 लाख रुपये है। सैन्य अस्पताल में बीडीएल द्वारा स्थापित ऑक्सीजन संयंत्रों में से एक सप्ताह में पांच दिन संचालित होता है, जो विभिन्न वार्डों में प्रतिदिन आपातकालीन रोगियों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसी तरह, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अपने बीडीएल-स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को लगातार संचालित करता है, मेडिकल, सर्जिकल और पल्मोनोलॉजी वार्डों में मरीजों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। मरीजों को उनकी उपचार आवश्यकताओं के आधार पर 5 से 15 एलपीएम तक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से प्रवाह 60-70 एलपीएम है।





ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बीडीएल द्वारा स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र में ऑक्सीजन दबाव, ऑक्सीजन शुद्धता और ऑक्सीजन प्रवाह मान

ऑक्सीजन संयंत्र निम्नलिखित चार मानदंडों को पूरा करते हैं:

- ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है
- लंबे समय में लागत प्रभावी।
- बाहरी स्रोतों से स्वतंत्रता प्रदान करता है
- विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन

प्रभावशीलता: यह परियोजना रोगियों के इलाज के लिए दोनों अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति के इष्टतम स्तर के वांछित परिणाम देने में सफल रही। अस्पताल-वार लाभार्थी विवरण नीचे दिया गया है।



सिकंदराबाद के सैन्य अस्पताल में आपातकालीन वार्डों में से एक को ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है

पैरामीटर	सैन्य अस्पताल	ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
लाभार्थी अस्पताल के वार्ड	आईसीयू, श्वसन आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, उच्च निर्भरता इकाई (एचडीयू), मेडिकल वार्ड, जनरल मेडिसिन वार्ड, परिवार वार्ड	ओपीडी ब्लॉक - मेडिकल, सर्जिकल और पल्मोनोलॉजी वार्डों के लिए उपयोग करना
प्रत्येक ऑक्सीजन प्लांट से जुड़े बेड की कुल संख्या	330 बिस्तर	200 बिस्तर
संयंत्र कार्य विवरण	5 दिन (24 X7)	24 X 7
लाभार्थी रोगी	40 क्रिटिकल केयर / सर्जरी रोगी प्रति दिन	40 क्रिटिकल केयर / सर्जरी रोगी प्रति दिन
विभिन्न उपचारों के लिए ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग	1)सीओपीडी (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) 2) आपातकालीन उपचार - विषाक्तता और आघात देखभाल सहित दुर्घटनाएं और आपातकालीन सेवाएं 3)ऑपरेशन थियेटर (चिकित्सा और शल्य चिकित्सा आपात स्थिति) 4) प्रसूति एवं स्त्री रोग 5) नवजात शिशु की देखभाल 6) हृदय और गुर्दे के रोगी 7) अस्थमा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (LRTI) 8) पोस्ट-ऑपरेटिव सर्जिकल रोगी	1) कम श्वसन संक्रमण (एलआरआई) 2)व्हीज़ एसोसिएटेड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (डब्ल्यूएलआरआई) 3)क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) 4) श्वसन संकट सिंड्रोम 5) निमोनिया और ब्रोंकाइटिस

प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने हमारी स्वास्थ्य प्रणाली और इसके वितरण प्रोटोकॉल को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत किया है। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना और ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली जैसी चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान ने तेलंगाना में सैन्य अस्पताल और ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया है, ताकि सशस्त्र बल कर्मियों, ईएसआई-बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न रोगियों का समय पर इलाज किया जा सके। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का जबरदस्त बोझ ऑक्सीजन संयंत्रों द्वारा कम किया गया था, जिसने अस्पतालों को गंभीर रूप से बीमार रोगियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को प्रबंधित करने और बचाने की अनुमति दी थी, जिन्हें 92-96% के संतृप्ति ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने के लिए पांच से पंद्रह एलपीएम की दर से ऑक्सीजन की आवश्यकता थी।

परियोजना के प्रमुख प्रभाव हैं

- तेलंगाना राज्य में सैन्य अस्पताल और ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, बीडीएल द्वारा वित्त पोषित, ने आपदाओं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए सुविधाओं को काफी मजबूत किया है।
- इन ऑक्सीजन संयंत्रों को COVID-19 की दूसरी लहर के कम होने के बाद चालू किया गया था और बढ़ी हुई ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।



सम्बद्धता: बीडीएल और कई पीएसयू ने ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना और विभिन्न कोविड-19 राहत उपायों को लागू करके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ाने के लिए सहयोग किया। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, बीडीएल ने पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने और कोविड रोगियों के जीवन को बचाने के लिए तेलंगाना और अन्य स्थानों पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए।

परिणाम

- तेलंगाना राज्य में सैन्य अस्पताल और ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया गया।
- ईएसआई अस्पताल और सैन्य अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के बाद, बीडीएल द्वारा आपूर्ति किए गए ऑक्सीजन संयंत्रों के कारण दोनों अस्पतालों की बाहर से ऑक्सीजन खरीदने पर निर्भरता कम हो गई थी।
- इस परियोजना ने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता को सक्षम किया, जो अस्पतालों को किसी भी भयावह स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना करने में मदद कर सकता है।

स्थिरता: महत्वपूर्ण वार्डों में रोगियों को उच्चतम संभव ऑक्सीजन स्तर प्रदान करने की ऑक्सीजन संयंत्रों की क्षमता के कारण परियोजना के परिणामों का स्थायी प्रभाव पड़ता है। दोनों अस्पताल ऑक्सीजन संयंत्रों के दैनिक रखरखाव और संचालन की देखरेख के लिए तकनीकी कर्मियों को समर्पित करते हैं। इसके अलावा, दोनों अस्पताल ऑक्सीजन संयंत्रों के पूर्ण रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए एएमसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में वृद्धि होती है और उनके जीवनकाल को बढ़ाया जाता है।

परियोजना का प्रदर्शन

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

सैन्य अस्पताल			ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल		
डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर	डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर
प्रासंगिकता	औसत से ऊपर	16	प्रासंगिकता	अति उत्कृष्ट	17
दक्षता	औसत से ऊपर	16	दक्षता	अति उत्कृष्ट	18
प्रभावशीलता	औसत से ऊपर	16	प्रभावशीलता	अति उत्कृष्ट	17
प्रभाव	औसत से ऊपर	16	प्रभाव	अति उत्कृष्ट	17
स्थिरता	औसत से ऊपर	16	स्थिरता	अति उत्कृष्ट	18
कुल स्कोर	औसत से ऊपर	80	कुल स्कोर	अति उत्कृष्ट	87

व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत खराब: 1 to 4

कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत खराब (1 to 20)

संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

आईपीई टीम ने सैन्य अस्पताल के पांच स्वास्थ्य अधिकारियों और ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पांच स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा की, जिनमें से सभी ने विभिन्न चिकित्सा उपचारों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन के

बढ़ते स्तर के साथ संतोष व्यक्त किया। इस वृद्धि ने दोनों अस्पतालों को अधिक रोगियों को स्वीकार करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस प्रकार का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा दोनों अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति करके किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस परियोजना के कारण, दोनों अस्पतालों ने बाहरी स्रोतों से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की आवश्यकता कम कर दी है।

समग्र अवलोकन

- बीडीएल ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और सैन्य अस्पताल में स्थित ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए स्थायी शेड सुविधाएं स्थापित की हैं।
- दोनों अस्पतालों ने पौधों के उचित रखरखाव और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक वार्षिक रखरखाव अनुबंध में प्रवेश किया है, विस्तारित अवधि के लिए ऑक्सीजन उत्पादन के इष्टतम स्तर को बनाए रखा है।
- दोनों अस्पतालों में तकनीकी कर्मचारियों ने पीएसए संयंत्रों को नियमित रूप से संचालित करने और बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण लिया है, संयंत्र के मोड की निगरानी और ऑक्सीजन की शुद्धता का निरीक्षण करने जैसे नियमित कार्यों को पूरा किया है।
- ये ऑक्सीजन संयंत्र पूरी तरह से चालू हैं, जो गंभीर देखभाल वाले रोगियों की उपचार अवधि के दौरान ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट चौबीसों घंटे संचालित होता है, जबकि सैन्य अस्पताल का संयंत्र सप्ताह में पांच दिन ऑक्सीजन थेरेपी से गुजरने वाले रोगियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन स्तर प्रदान करने के लिए कार्य करता है।

केस स्टडीज


केस स्टडी 1

श्री सिरिनिवास (बदला हुआ नाम), ईएसआईसी-बीमित व्यक्ति, एक 48 वर्षीय व्यक्ति, ने क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) के लिए ईएसआईसी अस्पताल में इलाज की मांग की। इस स्थिति के कारण फेफड़ों में वायु प्रवाह में रुकावट होती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई, खांसी, थूक का उत्पादन और एक विस्तारित अवधि में घरघराहट होती है। एक व्यापक निदान के बाद, डॉक्टर ने ईएसआईसी अस्पताल में पांच दिनों की अवधि के लिए 15 एलपीएम की क्षमता वाले बीडीएल-स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति का उपयोग करके विभिन्न परीक्षण किए, उचित दवाएं निर्धारित कीं और ऑक्सीजन थेरेपी शुरू की। इन सहयोगी प्रयासों के माध्यम से, सिरिनिवास ने दस दिनों के भीतर रक्त ऑक्सीजन के स्तर में सुधार, संक्रमण को कम करने और सीओपीडी से सफल वसूली का अनुभव किया।

परियोजना 7: ईएसआईसी, सनत नगर, हैदराबाद में कोविड पृथक्करण सुविधाओं की स्थापना

परियोजना का नाम	ईएसआईसी, सनत नगर, हैदराबाद में कोविड पृथक्करण सुविधाओं की स्थापना
परियोजना लागत	170 लाख
निष्पादन अवधि	2021-22



सीएसआर विषयगत क्षेत्र	अनुसूची VII, धारा 135 मद सं. (i): स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना मद सं. (xii): आपदा प्रबंधन – कोविड 19 राहत उपाय
एसडीजी लक्ष्य	
परियोजना का उद्देश्य	परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने और पात्र सामान्य और ईएसआईसी-बीमित रोगियों को अधिकृत कार्ड एक्सेस के माध्यम से कोविड -19 या गैर- कोविड उपचार का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए सनथनगर में ईएसआईसी अस्पताल के भीतर आठ प्रमुख रणनीतिक स्थानों पर फ्लैप बाधाओं का निर्माण करना है।
कुल लाभार्थी	ईएसआईसी अस्पताल योजना के लाभार्थी मरीज।

परियोजना की पृष्ठभूमि

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (ईएसआईसी एमसी एंड एच), सनथनगर, हैदराबाद, तेलंगाना में ईएसआई योजना के तहत कवर किए गए 14 लाख से अधिक बीमित व्यक्तियों के लिए 800 बिस्तर वाला अस्पताल है। कोविड के दौरान इस अस्पताल ने कोविड और गैर-कोविड दोनों सेवाएं प्रदान की हैं। इस अस्पताल में हर दिन 2400 से अधिक मरीजों की आमद होती है। गैर-कोविड रोगियों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए जहां कोविड -19 रोगियों का इलाज किया जा रहा था, ईएसआईसी एमसी-एच ने परिसर में विभिन्न आठ रणनीतिक स्थानों पर फ्लैप बैरियर स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, उन्होंने कोविड-19 आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सीएसआर फंडिंग के लिए बीडीएल से संपर्क किया और इसके परिणामस्वरूप, आठ फ्लैप बैरियर सफलतापूर्वक स्थापित किए गए। फ्लैप बैरियर ने कोविड और गैर-कोविड उपचार क्षेत्रों में रोगियों और रोगियों के तीमारदारों के प्रवाह को कम करने में सहायता की, जबकि केवल उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति देने वालों को पहुंच प्रदान की।

सभी कर्मचारियों को आरएफआईडी कार्ड/एक्सेस कार्ड दिए जाते हैं जो कर्मचारियों को अप्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति देते हैं। वर्तमान में, इन फ्लैप बैरियर का उपयोग परिसर में अधिक संख्या में अनधिकृत कर्मियों और अतिरिक्त रोगी परिचारकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे परिसर में इलाज किए जा रहे रोगियों के बीच संक्रमण की दर कम हो जाती है।

परियोजना की पहल

फ्लैप बैरियर निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं:

- मुख्य प्रवेश द्वार - बाईं ओर - 02 फ्लैप बैरियर
- मुख्य प्रवेश द्वार - दाईं ओर - 02 फ्लैप बैरियर
- सुपर स्पेशलिटी मुख्य द्वार प्रवेश - 02 फ्लैप बैरियर
- कॉलोनी द्वार - 01 फ्लैप बैरियर
- सुपर स्पेशलिटी निकास द्वार - 01 फ्लैप बैरियर

सुरक्षा कर्मी ईएसआईसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के मामले में परिसर में प्रवेश करने के लिए फ्लैप बैरियर के माध्यम से पहुंच प्रदान करने से पहले एक वैध बीमित व्यक्ति और उसके परिचर का सत्यापन करते हैं।



ईएसआईसी एमसी एंड एच – सनत नगर ने बीडीएल सीएसआर फंड के माध्यम से अपने परिसर में एक फ्लैप बैरियर स्थापित किया

प्रभाव विश्लेषण ढांचा: आईपीई टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के ओईसीडी डीएससी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं।

प्रासंगिकता

इस परियोजना में फ्लैप बाधाओं को शामिल करना अनधिकृत प्रवेश को रोकने और सामान्य और ईएसआईसी-बीमित व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित करने में आवश्यक साबित हुआ है, जिसमें कोविड और गैर-कोविड दोनों रोगी शामिल हैं। कार्ड एक्सेस को अधिकृत करके, पात्र ईएसआईसी-बीमित रोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड और गैर-कोविड उपचार प्राप्त करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश दिया गया था। वर्तमान में, यह परियोजना परिसर के भीतर कर्मचारियों, ईएसआईसी-बीमित रोगियों और उनके साथियों की गतिशीलता को सीमित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे परिसर के भीतर संक्रमण के संचरण को कम किया जा सकता है।

दक्षता: ईएसआईसी एमसी एंड एच ने बीडीएल सीएसआर निधि का उपयोग करते हुए निर्धारित बजट और समय सीमा के भीतर परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रत्येक फ्लैप बाधा सेवा जीवन 6 मिलियन से अधिक बार है, जो सामान्य खुले मोड में प्रति मिनट 35 से 40 लोगों के थ्रूपुट और सामान्य बंद मोड में प्रति मिनट 30 से 35 लोगों की अनुमति देता है। यह बुनियादी संचालन द्वारा सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से पहुंच को नियंत्रित करने और अवैध रूप से अंदर और बाहर रोकने के लिए एक उन्नत ऑपरेशन प्रदान करता है। फ्लैप बैरियर अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया, जंगरोधी और टिकाऊ है। वर्तमान में अधिकृत कार्ड एक्सेस और चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से

ईएसआईसी-बीमित रोगियों और स्टाफ सदस्यों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए फ्लैप बाधाओं का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। फ्लैप बैरियर टर्नस्टाइल नियमित आधार पर ईएसआईसी-बीमित रोगियों और कर्मचारियों के प्रवेश और निकास की देखरेख के लिए एक कुशल उपकरण के रूप में कार्य करता है।

प्रभावशीलता: ईएसआईसी एमसी एंड एच ने अनधिकृत व्यक्तियों या ईएसआईसी-बीमित रोगियों के अत्यधिक परिचारकों के लिए पहुंच को नियंत्रित करने और रणनीतिक स्थानों पर 8 फ्लैप बाधाओं को लागू करके कर्मचारी उपस्थिति की निगरानी के अपने परियोजना उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। ये फ्लैप बैरियर नियंत्रकों से जुड़ी होती हैं जो लगातार अपनी कनेक्टिविटी की निगरानी करती हैं और एक्सेस के लिए उपयोग किए जाने वाले आरएफआईडी कार्ड से डेटा संचारित करती हैं। नियंत्रक आईटी सर्वर रूम में दो सर्वरों से जुड़े होते हैं, आवश्यकतानुसार विश्लेषण के लिए एक्सेस विवरण संग्रहीत करते हैं। इसके अतिरिक्त, एप्लिकेशन उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली के लिए एक बैकअप के रूप में कार्य करता है, फ्लैप बाधाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले एक ही एप्लिकेशन द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर कर्मचारी उपस्थिति के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करता है।

प्रभाव: कार्यक्रम के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जैसे ईएसआईसी-बीमित व्यक्तियों और उनके साथियों की पहुंच के लिए ईएसआईसी एमसी एंड एच में निगरानी प्रणाली में सुधार, अनधिकृत प्रवेश की रोकथाम और कर्मचारी समय की पाबंदी को बढ़ावा देना। इन संवर्द्धन ने ईएसआईसी-बीमित रोगियों के डेटा, कर्मचारी दक्षता के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को अनुकूलित करके परिचालन लागत को कम किया है। यह पहल कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद थी, क्योंकि इसने कार्ड एक्सेस सिस्टम के माध्यम से विशेष रूप से पात्र सामान्य और ईएसआईसी-बीमित व्यक्तियों के लिए उपचार की अनुमति देकर कोविड -19 और गैर- कोविड -19 दोनों रोगियों के प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया, जिसके परिणामस्वरूप परिसर में व्यक्तियों के बीच वायरस संक्रमण में कमी आई।

सम्बद्धता: परियोजना के कार्यान्वयन ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य नीतियों और कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन किया, जिसमें कोविड -19 के दौरान और बाद में अस्पताल की निगरानी प्रणालियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।

परिणाम

- सनत नगर में ईएसआईसी-बीमित रोगियों और ईएसआईसी एमसी एंड एच कर्मचारियों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उन्नत निगरानी प्रणाली अस्तित्व में आई है।

स्थिरता: परियोजना के परिणाम टिकाऊ हैं क्योंकि ईएसआईसी एमसी एंड एच में नियमित संचालन और रखरखाव कार्यों को संभालने के लिए सुरक्षा कर्मी हैं। इन कार्यों में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और उपकरण के जीवनकाल को आगे बढ़ाने के लिए स्विंग/फ्लैप बैरियर गेट्स की सफाई बनाए रखना शामिल है। सुरक्षाकर्मी टर्नस्टाइल हाउसिंग और टर्नस्टाइल गेट के कार्ड रीडर पैनल की सफाई पर भी ध्यान देते हैं। इसके अलावा, वे आंतरिक आवागमन संरचना को चिकनाई करते हैं, ड्राइवर बोर्ड पर धूल का निरीक्षण और सफाई करते हैं, और विश्वसनीयता के लिए कनेक्टर्स और वायरिंग बिंदुओं की जांच करते हैं। ये आवश्यक क्रियाएं डिवाइस के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, अंततः परियोजना की दीर्घकालिक सफलता में योगदान करती हैं।

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर
प्रासंगिकता	अति उत्कृष्ट	18
दक्षता	अति उत्कृष्ट	17
प्रभावशीलता	अति उत्कृष्ट	17
प्रभाव	अति उत्कृष्ट	17
स्थिरता	अति उत्कृष्ट	17
कुल स्कोर	अति उत्कृष्ट	86

व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत खराब: 1 to 4

कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत खराब (1 to 20)

संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और सुरक्षा कर्मी: आईपीई टीम को चार प्रमुख अधिकारियों और 10 सुरक्षा कर्मियों के साथ जुड़ने का अवसर मिला, जिनमें से सभी ने अनधिकृत व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने और कोविड -19 महामारी के दौरान रोगियों के परिचारकों की आमद को नियंत्रित करने के उपायों के कार्यान्वयन के साथ अपनी उच्च संतुष्टि व्यक्त की। इन व्यक्तियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान निगरानी तंत्र के रूप में फ्लैप बाधाओं की प्रभावशीलता पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने आठ प्रवेश बिंदुओं पर आरएफआईडी कार्ड एक्सेस सिस्टम के उपयोग के माध्यम से सामान्य और ईएसआईसी-बीमित दोनों रोगियों की पहुंच को सफलतापूर्वक विनियमित किया। ईएसआईसी एमसी एंड एच ने कोविड -19 परीक्षण और उपचार प्रक्रियाओं पर महत्व दिया, जिससे फ्लैप बाधाओं के माध्यम से सामान्य और ESIC-बीमित व्यक्तियों दोनों सहित पात्र रोगियों तक अधिकृत पहुंच की अनुमति मिली। इसके अतिरिक्त, टीम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन फ्लैप बाधाओं के भीतर एकीकृत चेहरे की पहचान तकनीक के उपयोग के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति की बारीकी से निगरानी की गई थी।

समग्र अवलोकन

- सुरक्षा कार्मिक आरएफआईडी एक्सेस कार्डों का उपयोग करके ईएसआईसी-बीमित रोगियों को पहुंच की अनुमति दे रहे हैं, जो रोगियों के ईएसआईसी बीमा कार्ड और आधार कार्ड को सत्यापित करने के बाद जारी किए जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रभावी रूप से अनधिकृत व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने से रोकती है। वर्तमान में, आने वाले ईएसआईसी-बीमित रोगियों की संख्या सामान्य सीमा के भीतर है।
- भविष्य की किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में फ्लैप बैरियर विशेष रूप से अधिक फायदेमंद होंगी, क्योंकि वे रोगी प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और केवल पात्र रोगियों को स्वीकार करते हैं।
- यह प्रणाली ईएसआईसी एमसी और एच के पूरे परिसर में सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए निर्धारित है।



केस स्टडीज

केस स्टडी 1

“बीडीएल की परियोजना के कार्यान्वयन का कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सामान्य और ईएसआईसी-बीमित रोगियों की आमद के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। परियोजना से पहले, चिकित्सा ध्यान देने वाले रोगियों की संख्या भारी थी, जिससे व्यवस्था बनाए रखने और रोगियों और कर्मचारियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता थी। सुरक्षाकर्मियों के प्रयासों के बावजूद, लंबी कतारों और रोगियों के बीच भ्रम के साथ स्थिति नियंत्रण से बाहर होती रही। हालांकि, चिकित्सा सुविधा के भीतर आठ प्रमुख स्थानों पर फ्लैप बाधाओं की स्थापना के साथ, सामान्य और ईएसआईसी-बीमित रोगियों के बीच कोविड-19 रोगियों के लिए पहुंच को सुव्यवस्थित किया गया है। फ्लैप बैरियर अधिकृत कार्ड एक्सेस की अनुमति देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है जिन्हें कोविड -19 और गैर- कोविड के उपचार की आवश्यकता होती है। इसने पहले अनुभव की जाने वाली भीड़ और अराजकता को बहुत कम कर दिया है, क्योंकि रोगी अब आसानी से कोविड -19 उपचार के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं।

ईएसआईसी एमसी एंड एच वर्तमान में फ्लैप बाधाओं की निगरानी प्रक्रिया की देखरेख कर रहा है। सिस्टम के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण रही है, और वे इस तकनीक की मदद से रोगियों के प्रवाह को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम हैं।

कुल मिलाकर, फ्लैप बाधाओं की स्थापना कोविड -19 महामारी के दौरान रोगियों की आमद के प्रबंधन में एक गेम-चेंजर रही है। इसने न केवल चिकित्सा सुविधा की दक्षता में सुधार किया है बल्कि रोगियों और कर्मचारियों दोनों की सुरक्षा और कल्याण को भी बढ़ाया है। इस परियोजना की सफलता महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव समाधानों को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डालती है”।

चिकित्सा अधीक्षक

ईएसआईसी एमसी और एच

About the Centre for Corporate Social Responsibility (CCSR), IPE

The Centre for Corporate Social Responsibility (CCSR) was set up during 2011 to promote training, research, consultancy assignments and document case studies in thrust areas of CSR. The Centre works on the existing body of knowledge, systems, structures, models, and mechanisms associated with different CSR initiatives; it also provides a platform for discussing CSR guidelines and the latest developments in the field. The Institute of Public Enterprise (IPE) has been part of the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India initiative on introducing Corporate Social Responsibility (CSR) as an element of the performance matrix in Central Public Sector Enterprises (CPSEs). IPE was invited to attend the meetings of the Working Group on CSR in 2007-08 and 2009-10 and was nominated by DPE as a Member of the Executive Committee on CSR in 2011 to develop, design and implement courses for CPSEs. Recognizing the importance of the subject and the realization that there is a dearth of experts in this emerging field, it was decided that IPE could play a major role in research, development, and advocacy of CSR. This idea led to the establishment of the Center for Corporate Social Responsibility in 2011 at IPE. The main objectives of the center are:

- To conduct interdisciplinary and collaborative research and document case studies in thrust areas of CSR dealing with contemporary issues and challenges.
- To integrate the existing body of knowledge, systems, structures, models, and mechanisms associated with different CSR initiatives by interfacing with industry and academia.
- To disseminate information about the latest happenings in the CSR field to the people engaged in policy making, policy analysis, policy research, practitioners, and other stakeholders.

PROJECT LEADER

Prof S Sreenivasa Murthy

Director and NLCIL Chair Professor on CSR,
Institute of Public Enterprise
Hyderabad

PROJECT COORDINATOR

Dr J Kiranmai

Head, Center for CSR, and CG,
Institute of Public Enterprise
Hyderabad

TEAM MEMBERS

Mr M Vaman Reddy, Project Associate, IPE

Ms B Deepa, Research Associate, IPE

About Institute of Public Enterprise (IPE)

The Institute of Public Enterprise (IPE) was established in 1964 as an autonomous non-profit society. IPE is a premier AICTE approved management Institute focusing on transforming students into leaders of tomorrow in organizations and society. IPE's key objectives



include management education, research, consultancy, and training. In 1995, the Institute launched its first two year full-time Post Graduate Diploma in Management (PGDM) program to provide skilled human resources to meet the requirements of industry.

Keeping in view the market demand, the Institute also launched sector specific PGDM programs in the areas of Marketing, Banking Insurance and Financial Services, International Business and Human

Resource Management. IPE's engagement with long-term management education has received wide appreciation from the industry, government, and social sector enterprises. The Institute continuously endeavours to update the content and teaching methodology of its courses based on feedback from the end-users, ensuring the quality, relevance, and utility of all its programs and courses.

IPE is consistently ranked among the leading B-Schools in India in most well-known ranking surveys. IPE has also been awarded a premium accreditation label of the SAARC region, 'The South Asian Quality Assurance System' (SAQS). Over the years IPE has won several awards and honours for its academic & research excellence.

IPE has a very successful track record of running MDPs over a long period of time. IPE also has a strong Research and Consultancy division, which provide consulting services and undertakes research projects for various national organizations. The Institute has been recognized as a 'Center of Excellence' by the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), Ministry of Education, and Government of India.

The Governance of the Institute is overseen through a Board of Governors composed of eminent policy makers, academicians, and CEOs of public and private sector enterprises.



Survey No. 1266, Shamirpet V&M, Hyderabad - 500101.
Phone: +91-40-23490900 Fax: +91-040-23490999
www.ipeindia.org